ज्ञानामृत

यदि हमारे विचार सकारात्मक होंगे तो सब कुछ सकारात्मक हो जायेगा।

हंसराज सुज्ञ

राष्ट्र को समर्पित

विजय मत

मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र

www.vijaymat.com | भोपाल, शनिवार, 4 अप्रैल 2026 | वर्ष- 11 | अंक- 114 | पेज- 08 | मूल्य- ₹5.00/-

न्यूज इन शॉर्ट

हवाई किराया बढ़ाया तो सरकार दखल देगी, मीटिंग जल्द

नई दिल्ली, एजेंसी। एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी एटीएफ की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी के बाद कई एयरलाइंस ने फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया है। इससे यात्रियों पर बढ़ते बोझ को देखते हुए केंद्र सरकार अब इस मामले में हस्तक्षेप करने की तैयारी में है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार जल्द ही एयरलाइंस के साथ मीटिंग कर सकती है ताकि आम लोगों को महंगे सफर से राहत मिल सके। सरकार ने अभी तक कोई लिखित निर्देश तो जारी नहीं किया है, लेकिन एयरलाइंस से उनकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को लेकर स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यात्री किरायों में बढ़ोतरी न हो। एटीएफ की कीमतों में हाल ही में सोझ समझकर बढ़ोतरी की गई थी।

फ्लाइट में 60% सीटें मुफ्त देने के फैसले पर रोक

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने एयरलाइंस को फ्लाइट में 60% सीटें बिना अतिरिक्त शुल्क के चुनने देने वाले निर्देश को अस्थायी रूप से रोक दिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि यह नियम 20 अप्रैल से लागू होना था, लेकिन अब इसे अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 15 दिन पहले 18 मार्च को कहा था कि डीजीसीए को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी फ्लाइट में सीट चयन के लिए न्यूनतम 60% सीटें बिना चार्ज उपलब्ध कराई जाएं। इसका उद्देश्य यात्रियों को सीट चुनने में समान अवसर देना बताया गया था। मंत्रालय के अनुसार, इस मुद्दे की समीक्षा के दौरान फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस की ओर से आपत्तियां भेजी गईं।

सज्जादानशीन वक्फ़ में धार्मिक प्रमुख, मुतवल्ली सिर्फ प्रशासक

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि "सज्जादानशीन" और "मुतवल्ली" के पद एक समान नहीं हैं। अदालत ने कहा कि सज्जादानशीन वक्फ का आध्यात्मिक प्रमुख होता है और उसकी नियुक्ति पूरी तरह धार्मिक विषय है, जबकि मुतवल्ली की भूमिका केवल प्रशासन और प्रबंधन तक सीमित रहती है। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और विपुल एम पंचोली की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि सज्जादानशीन का पद आमतौर पर वंशानुगत होता है और संस्थापक को अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त करने का अधिकार होता है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वक्फ अधिनियम के तहत नियुक्त सज्जादानशीन, मुतवल्ली का कार्य भी संभाल सकते हैं, लेकिन मुतवल्ली को सज्जादानशीन का अधिकार नहीं दिया जा सकता।

पश्चिम बंगाल में मालदा हिंसा का मुख्य आरोपी अरेस्ट

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल के मालदा में एसआईआर से जुड़े न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने के मामले में मुख्य आरोपी समेत 35 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के 48 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी मोफक्करुल इस्लाम को बागडोगरा एयरपोर्ट से पकड़ा। वह बेंगलुरु भागने की फिराक में था। इस्लाम कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील है। वह 2011 में एआईएमआईएम का उम्मीदवार रह चुका है। मोफक्करुल पर आरोप है कि मालदा के सुजापुर में 1 अप्रैल को एसआईआर में नाम कटने के विरोध प्रदर्शन में भड़काऊ भाषण दिया। इससे लोग भड़क गए और हजारों लोगों ने कलियाचक के बीडीओ ऑफिस को घेर लिया। दो गेट बंद कर दिए गए, जिससे 7 न्यायिक अधिकारी 9 घंटे ऑफिस के अंदर बंधक रहे।

वाराणसी में तीन दिवसीय सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य के मंचन के शुभारंभ पर बोले सीएम मोहन...

प्रधानमंत्री के सुशासन में विक्रमादित्य युग की झलक स्वाभाविक

विजय मत, भोपाल

काशी की पावन धरती पर तीन दिवसीय 'सम्राट विक्रमादित्य' महानाट्य का भव्य शुभारंभ हुआ, जिसमें मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य सुशासन, न्यायप्रियता और राष्ट्र गौरव के प्रतीक रहे हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में उसी सुशासन की अनुभूति स्वाभाविक रूप से होती है। उन्होंने कहा कि काशी, जो प्रधानमंत्री की कर्मस्थली है, वहां इस महानाट्य का मंचन विशेष महत्व रखता है। यह आयोजन केवल सांस्कृतिक प्रस्तुति नहीं, बल्कि भारत की गौरवशाली परंपरा को जीवंत करने का प्रयास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के बीच यह कार्यक्रम सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करेगा तथा दोनों राज्यों के बीच सहयोग को नई दिशा देगा। मुख्यमंत्री ने केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री के सुशासन का उदाहरण है, जो राज्यों के बीच समन्वय और विकास को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य के आदर्श–न्याय, पराक्रम और प्रजा-हित–आज भी प्रासंगिक हैं और युवा पीढ़ी को उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि महानाट्य के माध्यम से सम्राट विक्रमादित्य के जीवन, उनके शासन और भारतीय ज्ञान परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि सम्राट विक्रमादित्य का शासनकाल भारतीय इतिहास में सुशासन का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जिस प्रकार विकास, पारदर्शिता और जनकल्याण की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वह उसी परंपरा का आधुनिक स्वरूप प्रतीत होता है। राज्यों के बीच सहयोग, बड़ी विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन और सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण, ये सभी पहलू इस बात को दर्शाते हैं कि भारत अपने गौरवशाली अतीत की ओर लौटते हुए आधुनिकता के साथ आगे बढ़ रहा है।

महानाट्य के माध्यम से सम्राट विक्रमादित्य के जीवन से युवा पीढ़ी परिचित हो रही है: मोहन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह महानाट्य युवा पीढ़ी को सम्राट विक्रमादित्य के जीवन, उनके आदर्शों और उनके योगदान से परिचित कराने का प्रभावी माध्यम बन रहा है। उन्होंने बताया कि इस नाट्य में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और अन्य पेशों से जुड़े लोग कलाकार बनकर मंच पर प्रस्तुति दे रहे हैं, जिससे समाज की भागीदारी भी सुनिश्चित हो रही है। नाटक में सम्राट के न्याय, पराक्रम और प्रजा के प्रति समर्पण को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इससे दर्शकों को न केवल मनोरंजन मिलता है, बल्कि वे अपने इतिहास और संस्कृति के प्रति गौरव भी महसूस करते हैं। यह आयोजन लोकरंजन के साथ-साथ राष्ट्र निर्माण की भावना को भी सशक्त करता है।

दो राज्यों के मध्य सांस्कृतिक संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के बीच ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध सदियों पुराने हैं, जिन्हें यह आयोजन और मजबूत कर रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों राज्य विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं और यह महानाट्य सांस्कृतिक आदान-प्रदान का सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। काशी और उज्जैन, दोनों ही आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र हैं और इनका आपसी जुड़ाव देश की सांस्कृतिक एकता को दर्शाता है। इस प्रकार के आयोजन न केवल परंपराओं को जीवित रखते हैं, बल्कि नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का कार्य भी करते हैं, जिससे राष्ट्रीय एकता और समरसता को बल मिलता है।

महानाट्य का भव्य मंचन बना आकर्षण का केंद्र

वाराणसी में आयोजित इस महानाट्य का मंचन भव्यता और तकनीकी उत्कृष्टता का अद्भुत उदाहरण रहा। लगभग 400 कलाकारों ने मंच पर जीवंत अभिनय करते हुए सम्राट विक्रमादित्य के जीवन को साकार किया। विशाल सेट, ऊंचे दुर्ग, हाथी-घोड़े और आधुनिक प्रकाश-संगीत संयोजन ने दर्शकों को हजारों वर्ष पुराने स्वर्णिम युग में पहुंचा दिया। युद्ध के दृश्य, न्याय के प्रसंग और विक्रम संवत की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम स्थल पर दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी और "जय महाकाल" तथा "सम्राट विक्रमादित्य" के जयकारों से वातावरण गुंजायमान हो उठा। यह महानाट्य केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की ऐतिहासिक चेतना को पुनर्जीवित करने वाला एक सशक्त माध्यम बनकर सामने आया।

केरल चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को संदेश

संजू सैमसन से सीखें मुश्किल वक्त में वापसी करना : पीएम नरेंद्र मोदी

तिरुवनंतपुरम, एजेंसी

केरल विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते हुए भारतीय क्रिकेटर संजू सैमसन का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों में मजबूत वापसी कैसे की जाती है, यह सैमसन से सीखा जा सकता है। शुक्रवार को कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने टी20 विश्व कप 2026 में सैमसन के प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि आलोचनाओं के बावजूद खुद पर भरोसा बनाए रखना और सही समय पर सर्वश्रेष्ठ देना ही असली खिलाड़ी की पहचान है। प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे भी चुनाव में इसी आत्मविश्वास और जज्बे के साथ जुटें। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने, घर-घर संपर्क अभियान तेज करने और हर कार्यकर्ता को सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

राहुल गांधी बनाम कार्तिकेय मामला हाईकोर्ट पहुंचा, मानहानि केस में समन को चुनौती

विजय मत, ब्यूरो जबलपुर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय चौहान के बीच चल रहा मानहानि विवाद अब मध्यप्रदेश हाईकोर्ट पहुंच गया है। राहुल गांधी ने भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा जारी समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। यह मामला वर्ष 2018 का है, जब राहुल गांधी ने झाबुआ की एक चुनावी सभा में पनामा पेपर लीक का जिक्र करते हुए शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे पर आरोप लगाए थे।

ईरान का अमेरिकी पायलट को हिरासत में लेने से इनकार, कहा-

एफ-35 फाइटर जेट गिराया, पूरे इलाके में अमेरिकी ठिकाने तबाह करने की धमकी

तेल अवीव/वॉशिंगटन, एजेंसी

ईरान ने दावा किया है कि उसने शुक्रवार को एक अमेरिकी एफ-35 फाइटर जेट गिरा दिया है। हालांकि उसके पायलट को हिरासत में लेने की खबरों से इनकार कर दिया। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि इस जेट का पायलट ईरान की हिरासत में है। रिपोर्ट के मुताबिक, विमान गिरने से पहले पायलट ने कूदकर अपनी जान बचाई और वह ईरान के अंदर ही कहीं उतरा। अपने पायलट को ढूंढने के लिए अमेरिकी सेना ने कोहगिलुयेह और बोयेर-अहमद जिले में सर्च ऑपरेशन चलाया।

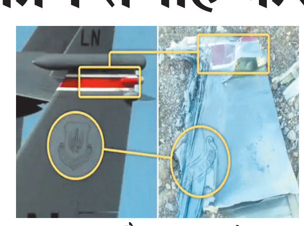

हम अकेले जिसने होर्मुज में नाविक खोए: भारत

ब्रिटेन की पहल पर होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए गुरुवार को एक ऑनलाइन बैठक हुई, जिसमें 60 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में भारत की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिसरी शामिल हुए। बैठक में विक्रम मिसरी ने कहा कि होर्मुज संकट में अब तक सिर्फ भारत के ही नागरिक मारे गए हैं।

अरिदमन पनडुब्बी नौसेना में शामिल, भारत की समुद्री शक्ति हुई मजबूत

विशाखापत्तनम, एजेंसी

भारत की रक्षा क्षमता को मजबूती देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित नौसेना कार्यक्रम में स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी 'अरिदमन' को भारतीय नौसेना में शामिल किया। बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्रों से लैस यह देश की तीसरी परमाणु पनडुब्बी है, जिससे भारत की समुद्री सुरक्षा और परमाणु प्रतिरोधक क्षमता में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है। कार्यक्रम से पहले रक्षा मंत्री ने अपने सामाजिक माध्यम पर कहा ÷शब्द नहीं, शक्ति है 'अरिदमन'। यह पनडुब्बी पानी के भीतर लगभग 44 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है और इसका पता लगाना कठिन माना जाता है। इसमें के-15 और के-4 जैसे घातक प्रक्षेपास्त्र लगाए गए हैं।

एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा 6 संस्थान बने स्वायत्त शैक्षणिक इकाइयां

नई दिल्ली, एजेंसी

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश पर 30 जनवरी को इसकी अधिसूचना जारी की। इस निर्णय के बाद परिषद के अंतर्गत संचालित छह प्रमुख संस्थान अब मानित विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेंगे। इनमें अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलांग स्थित क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान शामिल हैं। इसके साथ ही भोपाल स्थित पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान को भी यह दर्जा दिया गया है। मानित विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने के बाद इन संस्थानों को शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों में अधिक स्वायत्तता प्राप्त होगी। अब ये संस्थान अपने पाठ्यक्रम तैयार कर सकेंगे, शोध कार्य को बढ़ावा दे सकेंगे और नई शैक्षणिक पहल शुरू कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि इस फैसले से शिक्षक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। साथ ही यह कदम देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा।

ईरान से जंग के बीच ट्रंप बोले- तेल पर कब्जा कर कमाएंगे मुनाफा

बस कुछ समय और फिर खुल जाएगा होर्मुज

वॉशिंगटन, एजेंसी

पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के दबाव में झुकने के तैयार नहीं है। इसी बीच उनका एक बड़ा बयान सामने आया। ट्रंप ने कहा है कि अगर थोड़ा और समय मिला तो अमेरिका होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोल सकता है और वहां से तेल लेकर बड़ा मुनाफा कमा सकता है। उनके इस बयान ने पहले से चल रहे संघर्ष को और संवेदनशील बना दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमेरिका के पास इतनी क्षमता है कि वह होर्मुज को खोलकर तेल आपूर्ति को फिर से चालू कर सकता है। फिलहाल ईरान ने इस अहम समुद्री रास्ते को बंद कर दिया है।

विजय मत एंकर नई शिक्षा नीति के तहत बड़ा बदलाव, 2026-27 से नए पाठ्यक्रम की घोषणा

सीबीएसई में तीन-भाषा व्यवस्था और दो-स्तरीय परीक्षा प्रणाली लागू

नई दिल्ली, एजेंसी

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से नई शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण बदलाव लागू करने की घोषणा की है। इसके तहत कक्षा 6 से तीन-भाषा व्यवस्था अनिवार्य की जाएगी, जबकि कक्षा 9 से गणित और विज्ञान विषयों में दो-स्तरीय परीक्षा प्रणाली लागू होगी। बोर्ड के अनुसार इन बदलावों का उद्देश्य विद्यार्थियों की समझ, विश्लेषण क्षमता और बहुभाषी दक्षता को मजबूत करना है। नई भाषा व्यवस्था में विद्यार्थियों को तीन भाषाएं पढ़नी होंगी, जिनमें से कम से कम दो भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। भाषाओं को प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाषा के रूप में व्यवस्थित किया गया है। हालांकि विदेश से लौटने वाले विद्यार्थियों को विशेष परिस्थितियों में छूट दी जा सकती है, लेकिन उन्हें विषयों की कुल संख्या पूरी करनी होगी। गणित और विज्ञान में दो-स्तरीय व्यवस्था लागू होगी, जिसमें सामान्य और उन्नत स्तर शामिल होंगे। सभी विद्यार्थियों के लिए सामान्य स्तर अनिवार्य रहेगा, जबकि उन्नत स्तर वैकल्पिक होगा। यह नई प्रणाली 2026-27 से कक्षा 9 में लागू होगी और इसी बैच के लिए 2028 में कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा नए स्वरूप में आयोजित की जाएगी।

तीन-भाषा व्यवस्था: कक्षा 6 से अनिवार्य तीसरी भाषा

नई व्यवस्था के तहत कक्षा 6 से विद्यार्थियों को तीन भाषाएं पढ़नी होंगी, जिनमें कम से कम दो भारतीय भाषाएं होंगी। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को देश की भाषाई विविधता से जोड़ना और उनकी संचार क्षमता को मजबूत करना है। इससे विद्यार्थियों में सांस्कृतिक समझ भी विकसित होगी और वे विभिन्न भाषाओं में दक्ष बन सकेंगे।

कक्षा 9 में गणित-विज्ञान का दो-स्तरीय सिस्टम

कक्षा 9 से गणित और विज्ञान विषयों में दो स्तर लागू किए जाएंगे। सामान्य स्तर की परीक्षा 80 अंकों की होगी और सभी के लिए अनिवार्य रहेगी। उन्नत स्तर 25 अंकों का होगा, जो विद्यार्थियों की गहरी समझ और विश्लेषण क्षमता को परखेगा। यह विकल्प उन विद्यार्थियों के लिए होगा जो विषय में अधिक दक्षता प्राप्त करना चाहते हैं।

उन्नत परीक्षा के अंक ऐसे होंगे दर्ज

बोर्ड के अनुसार उन्नत स्तर की परीक्षा के अंक कुल परिणाम में नहीं जोड़े जाएंगे। हालांकि यदि कोई विद्यार्थी इसमें 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करता है, तो इसे उसकी अंकसूची में अलग से दर्ज किया जाएगा। इससे विद्यार्थियों की अतिरिक्त योग्यता को मान्यता मिलेगी और उन्हें आगे की पढ़ाई में लाभ मिलेगा

अमेरिका-चीन तकनीकी टकराव तेज

चीन की चिप तकनीक पर रोक के लिए अमेरिकी संसद में 'मैच एक्ट' पेश

वॉशिंगटन, एजेंसी

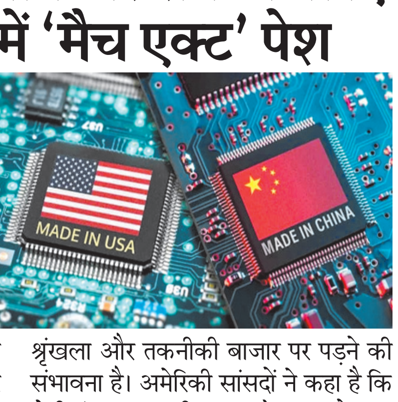

वैश्विक सेमीकंडक्टर और तकनीकी वर्चस्व की दौड़ के बीच अमेरिका ने चीन पर दबाव बढ़ाने के लिए 'मैच एक्ट' नामक नया विधेयक पेश किया है। इस कानून का उद्देश्य चीन और अन्य प्रतिद्वंद्वी देशों को उन्नत चिप निर्माण तकनीक तक पहुंचने से रोकना है। अमेरिकी सांसदों का मानना है कि मौजूदा निर्यात नियंत्रण व्यवस्था में कई खामियां हैं, जिनका फायदा उठाकर चीन तकनीक हासिल कर रहा है। प्रस्तावित कानून के तहत अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर एक समान निर्यात नियंत्रण नीति लागू करना चाहता है, ताकि तकनीक के हस्तांतरण पर सख्ती से रोक लगाई जा सके। इस कदम का सीधा असर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और तकनीकी बाजार पर पड़ने की संभावना है। अमेरिकी सांसदों ने कहा है कि सेमीकंडक्टर तकनीक अब केवल उद्योग का हिस्सा नहीं, बल्कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हो चुकी है। ऐसे में इसे सुरक्षित रखना राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम हिस्सा बन गया है।

प्रधान संपादक- विजय शुक्ला। कार्यालयः भोपाल ■ शहडोल ■ रायपुर ■ इंदौर ■ जबलपुर ■ होशंगाबाद ■ विदिशा ■ सीहोर ■ बैतूल ■ छिंदवाड़ा ■ ग्वालियर ■ ब्यौहारी ■ अनूपपुर ■ उमरिया ■ सीधी ■ सिंगरौली ■ रीवा ■ सतना ■ मैहर ■ खरगोन ■ बालाघाट ■ सिवनी ■ कटनी ■ सागर ■ मुलताई ■ मुरैना ■ टीकमगढ़

न्यूज इन शॉर्ट

ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति द्वारा सार्वजनिक प्याऊ की शुरुआत

जयसिंहनगर। मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के तत्वावधान में जिला समन्वयक विवेक पाण्डेय के निर्देशन एवं ब्लॉक समन्वयक ऋत्विकदास मिश्रा के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत बसोहरा अंतर्गत ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति बसोहरा द्वारा सार्वजनिक प्याऊं की शुरुआत हुई। सार्वजनिक प्याऊं से इस बढ़ती गर्मी के दौरान ग्रामीण जन एवं यात्रियों को निःशुल्क पेयजल की सुविधा मिल सकेगी। सार्वजनिक प्याऊं के शुभारंभ अवसर पर मौजूद ग्राम पंचायत बसोहरा के सरपंच दशरथ सिंह मरावी ने कहा कि यात्रियों एवं ग्रामीणजन को निःशुल्क रूप से पेयजल उपलब्ध हो सकेगा।? इस दौरान उपस्थित राहगीरों को चना एवं गुड़ भी खिलाया गया। सार्वजनिक प्याऊं के शुभारंभ अवसर पर उपस्थित दशरथ सिंह मरावी, प्रस्फुटन समिति के अध्यक्ष राजकुमार यादव, अमन कुमार गुप्ता, मुनीश सिंह मरावी, मान सिंह सहित अन्य ग्रामीण जन एवं ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति के सदस्य मौजूद रहे।

15 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं की खरीदी, 6 उपार्जन केंद्रों पर 980 किसान बेच सकेंगे उपज

अनूपपुर। जिले में रबी विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का काम 15 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। जिला प्रशासन ने इस बार जिले में कुल 6 उपार्जन केंद्र बनाए हैं, जहां पंजीकृत किसान अपनी फसल बेच सकेंगे। अब तक जिले के करीब 980 किसानों ने 20220.85 हेक्टेयर रकबे के लिए अपना पंजीयन कराया है। कलेक्टर हर्षल पंचोली ने उपार्जन केंद्रों पर व्यवस्थाएं चाक-चौबंद रहें, इसके लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को नोडल और पर्यवेक्षण अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है। ये अधिकारी न केवल केंद्रों पर सुविधाओं का सत्यापन करेंगे, बल्कि किसानों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण भी करेंगे। जिला आपूर्ति अधिकारी अनीता सोरते ने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए कृषि उपज मंडी अनूपपुर के लिए अंकित पवार, मां शारदा वेयरहाउस, बरबसपुर के लिए राजेश ब्राम्हणे, शारदा फूड प्रोसेसिंग, पयारी मझगवां (फुनगा) समिति के लिए महावीर सिंह मरावी, सिंह वेयरहाउस छातापटपर धनगवां समिति के लिए नरेन्द्र जमरा, बतूल वेयरहाउस कोतमा, बिजुरी समिति के लिए वैभव पारासर ओर स्वक्क्नस्ट गोदाम, राजेंद्रग्राम के लिए आराधना सोलंकी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। कलेक्टर ने सभी नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे उपार्जित फसल की गुणवत्ता, तौल और भंडारण की सतत निगरानी करें। साथ ही, केंद्रों पर छाया, पानी और किसानों के बैठने जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। उपार्जित गेहूं के समय पर उठाव (परिदान) के लिए भी विशेष कार्ययोजना तैयार की गई है।

सिर पर मंदिर रखकर नर्मदा परिक्रमा कर रहे महाराष्ट्र के प्रीतपाल

अमरकंटक। मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं आध्यात्मिक तीर्थ स्थल अमरकंटक में एक अनोखी और प्रेरणादायक नर्मदा परिक्रमा यात्रा देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के पुणे निवासी प्रीतपाल (उम्र लगभग 40 वर्ष) मां नर्मदा की भक्ति में लीन होकर अपने सिर पर काष्ठ से निर्मित मंदिर रखकर पैदल परिक्रमा कर रहे हैं।
इस विशेष मंदिर में त्रिदेव–ब्रह्मा, विष्णु और महेश–के साथ मां नर्मदा की प्रतिमा विराजित है। प्रीतपाल अपने दैनिक उपयोग की सामग्री पीठ पर बैग में रखकर कठिन तपस्या और हठयोग के साथ यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने अपनी परिक्रमा यात्रा ओंकारेश्वर धाम से प्रारंभ की थी और लगभग चार महीने की कठिन पदयात्रा के बाद अब अमरकंटक पहुंच चुके हैं। अमरकंटक में माई की बगिया पहुंचकर उन्होंने विधिवत पूजन-अर्चन, आरती एवं तट-जल परिवर्तन की प्रक्रिया पूर्ण की और मां नर्मदा के दक्षिण तट से अपनी आगे की यात्रा पुनः प्रारंभ कर दी है। नर्मदा परिक्रमा यात्री महाराष्ट्र के प्रीतपाल एक हाथ में दंड और कमंडल धारण किए, हंसते-मुस्कुराते हुए भजन-कीर्तन करते निरंतर आगे बढ़ रहे हैं।

अवैध प्लाटिंग के फेर में उजड़ी बिजली व्यवस्था, 3.85 लाख का नुकसान, विभाग की ढिलाई ने बढ़ाए सवाल

पेड़ काटने की लापरवाही से ट्रांसफार्मर जला, पोल टूटा – लेकिन विद्युत विभाग ने एफआईआर तक में दिखाई सुस्ती

विजय मत, अनूपपुर

कोतमा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 8 स्लामगंज में अवैध प्लाटिंग की आशंका के बीच पेड़ कटाई के दौरान हुई बड़ी लापरवाही ने पूरे इलाके की बिजली व्यवस्था को ठप कर दिया। इस घटना में विद्युत विभाग को लगभग 3.85 लाख रुपये का नुकसान हुआ, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात विभाग की कार्यप्रणाली रही, जिसने गंभीर घटना के बावजूद तत्काल कानूनी कार्रवाई करने में सुस्ती दिखाई।
जानकारी के अनुसार, 19 मार्च 2026 की शाम करीब 5¬45 बजे एक निजी बाड़े में नीम का पेड़ काटा जा रहा था। आरोप है कि यह पेड़ जमीन को प्लॉटिंग के लिए तैयार करने के उद्देश्य से हटाया जा रहा था। इसी दौरान पेड़ की भारी डगाल सीधे एलटी लाइन पर गिर गई, जिससे एक विद्युत पोल टूट गया, केबल जलकर नष्ट हो गई और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स क्षतिग्रस्त हो गया। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब शॉर्ट सर्किट के चलते ट्रांसफार्मर पूरी तरह खराब हो गया, जिससे पूरे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई।

तत्काल सुधार, लेकिन कार्रवाई में ढिलाई – विभाग की भूमिका संदिग्ध

घटना के बाद विद्युत विभाग ने तेजी दिखाते हुए तकनीकी खामियों को दुरुस्त कर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी, लेकिन कानूनी कार्रवाई के मामले में विभाग पूरी तरह फिसड्डी साबित हुआ। इतनी बड़ी क्षति और स्पष्ट लापरवाही के बावजूद अधिकारियों ने न तो मौके पर पुलिस को बुलाया और न ही तत्काल थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई। चौंकाने वाली बात यह है कि 5 दिन बाद 24 मार्च को एक औपचारिक पत्र डाक के माध्यम से थाना कोतमा भेजकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश की गई। सवाल यह है कि क्या विभाग सिर्फ कागजी कार्रवाई कर खुद को बचाने में लगा है?

अवैध प्लाटिंग का शक, प्रशासन मौन

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, जिस जमीन पर यह घटना हुई वहां अवैध प्लाटिंग की तैयारी लंबे समय से चल रही थी। बिना अनुमति पेड़ों की कटाई इसका हिस्सा बताई जा रही है। यदि ऐसा है, तो यह केवल विद्युत नुकसान नहीं बल्कि नियमों की खुली अनदेखी का मामला है। इसके बावजूद प्रशासन और संबंधित विभागों की चुप्पी कई संदेह पैदा करती है। आखिर बिना अनुमति पेड़ कटाई कैसे हो रही थी और किसके संरक्षण में यह काम चल रहा था?

लापरवाही या मिलीभगत? उठते बड़े सवाल

इस पूरे मामले ने विद्युत विभाग की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लगा दिए हैं– इतनी बड़ी घटना के बाद तत्काल एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई गई? क्या विभाग जानबूझकर दोषियों को बचाने की कोशिश कर रहा है? क्या अवैध प्लाटिंग के खेल में विभागीय स्तर पर भी कहीं न कहीं मिलीभगत है? विद्युत व्यवस्था को हुए नुकसान से ज्यादा चिंताजनक विभाग की निष्क्रियता और ढुलमुल रवैया है, जो यह संकेत देता है कि जिम्मेदार अधिकारी अपनी जवाबदेही से बचने में लगे हैं।

पुलिस जांच पर टिकी उम्मीदें

फिलहाल मामला थाना कोतमा में पहुंच चुका है, लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज होने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे में पूरे प्रकरण में अब पुलिस कार्रवाई ही तय करेगी कि दोषियों पर सख्त कदम उठते हैं या मामला कागजों में ही दबकर रह जाता है। यह घटना साफ तौर पर दर्शाती है कि लापरवाही, अवैध गतिविधियों और विभागीय ढिलाई का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में सख्ती दिखाता है या फिर यह मामला भी अन्य मामलों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा।

इनका कहना है

पेड़ काटने के दौरान पेड़ सीधे विद्युत लाइन पर गिरा ,जिससे दो पल विद्युत लाइन एवं ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुए जिन्हें तत्काल बदल गया मौके में पंचनामा भी बनाया गया । हमने डाक से शिकायत थाने को भेज दिया है अब इस पर पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई करेगी ।

आशुतोष चंद्रा
कनिष्ठ अभियंता कोतमा

डाक के माध्यम से हमें शिकायत मिली है हमने जान शुरू कर दिया है जांच के आधार पर शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने संबंधित धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जाएगी ।

रत्नांबर शुक्ला
थाना प्रभारी कोतमा

मप्र-छग की सीमा पहुंचा दो दांतों वाला हाथी, महुआ बीन रहे वृद्ध पर हमला, उतारा मौत के घाट

विजय मत, अनूपपुर

अनूपपुर के जैतहरी वन परिक्षेत्र से सटे छत्तीसगढ़ राज्य के मरवाही वनमंडल शिवानी बीट में एक दो दांतों वाले हाथी के आगमन ने फिर से जैतहरी के ग्रामीणों के साथ विभाग की चिंता बढ़ा दी है। जहां मरवाही के शिवनी बीट के ग्राम पंचायत पोंडी अंतर्गत डडिया गांव की जंगल में शुक्रवार की सुबह 4 बजे महुआ बीनने गए 55 वर्षीय वृद्ध पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया है। घटना की जानकारी पर वन विभाग के कर्मचारी, ग्राम पंचायत के सरपंच एवं ग्रामीण घटनास्थल पर मौजूद है।
वन विभाग आगे की कार्रवाई कर रहा है। हाथी फिलहाल डडिया के जंगल में ठहरा हुआ है, जिसके अनूपपुर वन मंडल की ओर बढ़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। बताया जाता है कि एक अकेला दो दांत वाला नर हाथी 2 अप्रैल की सुबह मरवाही वनमंडल एवं वन परिक्षेत्र गुल्लीडांड बीट के मालाकोट गांव से लगे जंगल में ठहरने बाद शाम घिनौची मुरूम खदान के पीछे से शुक्रवार की सुबह 4 बजे ग्राम पंचायत पोंडी एवं वन बीट शिवनी अंतर्गत डडिया के डडियाडोंगरी जंगल पहुंचा था। जहां 55 वर्षीय वृद्ध त्रिलोचन सिंह पिता अंगद सिंह जो अकेले महुआ फल संग्रहित करने के लिए जंगल में थे पर अचानक हाथी ने सुबह 4 बजे हमला कर दिया। जिससे वृद्ध की मौके पर मौत हो गई। घटना की जानकारी पर वनरक्षक बीट शिवनी शाहिद खान, ग्राम पंचायत पोंडी सरपंच हेमचंद मरावी एवं ग्रामीण जन घटना स्थल पर पहुंचे हैं। घटना की जानकारी मरवाही थाना को ग्रामीणों द्वारा दी गई है। दरअसल यह क्षेत्र मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिला अंतर्गत जैतहरी वन परिक्षेत्र के वन बीट एवं ग्राम पंचायत चोलना की सीमा से चार से पांच किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जैतहरी वन परिक्षेत्र अधिकारी विवेक मिश्रा ने बताया कि यह हाथी 2 मार्च की सुबह छत्तीसगढ़ राज्य के मरवाही वन मंडल एवं वन परिक्षेत्र की सीमा शिवनी बीट को पार कर अनूपपुर के जैतहरी पहुंचा था, जो अपने तीन अन्य हाथी साथियों जो धनगवां बीट के जंगल में ठहरे थे के साथ मिलकर विचरण किया और फिर झुंड से अलग निकलकर वन क्षेत्र कोतमा के पडौंर, चुकान, आमाडांड, मलगा, टांकी से विचरण करते हुए छत्तीसगढ़ के मनेद्रगढ़, खड़गवां वन परिक्षेत्र की ओर वापस अपने कटघोरा वन मंडल स्थित हाथियों के बड़े दल में जाकर मिल गया था। उसके एक बार फिर अपने तीन हाथी साथियों की तलाश में वापस आने की संभावना जताई जा रही है। वन विभाग द्वारा ग्रामीणों को दिन एवं रात के समय जंगल में महुआ बीनने, लकड़ी काटने, लेने तथा अन्य कार्यों के लिए जंगल नहीं जाने की हिदायत दी है।

बिजली कर्मचारियों का प्रांतव्यापी प्रदर्शन, 11 सूत्रीय मांगों को लेकर चचाई थर्मल प्लांट पर धरना

विजय मत, चचाई

मध्यप्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ के 11 सूत्रीय मांग पत्र के समर्थन में प्रांतव्यापी आंदोलन के तहत शुक्रवार को चचाई स्थित थर्मल पावर प्लांट के मुख्य द्वार पर सैकड़ों कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। सुबह 11 बजे शुरू हुआ यह धरना शाम 5¬30 बजे तक जारी रहा।
धरने में भामसं के अखिल भारतीय मंत्री एवं विद्युत प्रभारी आर. एस. जायसवाल और अखिल भारतीय विद्युत सेवानिवृत्त कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण देवांगन विशेष रूप से शामिल हुए। कर्मचारियों ने संविदा कर्मियों के नियमितीकरण, वेतन विसंगतियों को दूर करने, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, आउटसोर्स कर्मचारियों को ठेकेदारों के शोषण से मुक्ति दिलाने तथा ग्रेच्युटी राशि को केंद्र के अनुरूप 25 लाख रुपये करने सहित 11 मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया।धरनारत कर्मचारियों को संबोधित करते हुए आर. एस. जायसवाल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए श्रम कानूनों में श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के कई प्रावधान किए गए हैं, लेकिन कुछ बिंदुओं पर आपत्ति दर्ज कर संशोधन की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि ठेका श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम वेतन, नियुक्ति पत्र, स्वास्थ्य सुविधाएं और ओवरटाइम भुगतान सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।
वहीं अरुण देवांगन ने मध्यप्रदेश पावर कंपनी में कर्मचारियों को केंद्र के अनुरूप ग्रेच्युटी का लाभ न मिलने, वेतन संरक्षण नहीं दिए जाने और वरिष्ठ-कनिष्ठ वेतन में भारी विसंगतियों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि नियमित कर्मचारियों की कमी भी प्रशासनिक नीतियों की देन है, जिसे तत्काल सुधारने की जरूरत है।इस दौरान भामसं के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य ताराचंद यादव ने ठेका श्रमिकों के शोषण के खिलाफ संघर्ष तेज करने का आह्वान किया। कृषि एवं वनवासी ग्रामीण महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री कृष्ण कुमार बैगा तथा कोयला उद्योग के महेंद्र पाल ने भी कर्मचारियों की मांगों का समर्थन किया।
अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय मंत्री सतेन्द्र पाटकर ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन के तीसरे चरण में 16 अप्रैल को हजारों कर्मचारी भोपाल कूच कर विशाल रैली निकालेंगे।

मंत्री जायसवाल की पहल से बंद खदान बनी जल संकट का समाधान

विजय मत, अनूपपुर

भीषण गर्मी के बीच जल संकट से जूझ रहे बिजुरी नगर के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। मध्यप्रदेश शासन के राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल की सक्रियता और संवेदनशील पहल से नगर में पेयजल संकट के समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। बंद पड़ी खदान को जल स्रोत के रूप में उपयोग कर नगरवासियों तक पानी पहुंचाया जा रहा है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। जानकारी के अनुसार, नगर में बढ़ते जल संकट को देखते हुए मंत्री दिलीप जायसवाल ने हाल ही में नगर पालिका सभागार में अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर कॉलरी प्रबंधन को सख्त निर्देश दिए थे कि बंद खदानों में उपलब्ध जल का उपयोग आम जनता की जरूरतों के लिए किया जाए। मंत्री के निर्देश के बाद प्रशासन और कॉलरी प्रबंधन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वार्ड क्रमांक 14 लोहसारा स्थित बंद खदान में हैवी ड्यूटी पंप लगाकर जल निकासी शुरू की।

परीक्षण के दौरान खदान का पानी उपयोग योग्य पाया गया, जिसके बाद इसे नियमित जल आपूर्ति के लिए उपयोग में लाया जाने लगा। वर्तमान में नगर पालिका द्वारा प्रतिदिन 30 से 40 टैंकर पानी भरकर विभिन्न वार्डों और दूरस्थ मोहल्लों में पहुंचाया जा रहा है। इससे लंबे समय से पानी की समस्या झेल रहे नागरिकों को बड़ी राहत मिली है। जहां एक ओर बंद खदान से तत्काल राहत दी जा रही है, वहीं दूसरी ओर केवई नदी समूह जल प्रदाय योजना का कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है।

जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने जताया आभार

मंत्री दिलीप जायसवाल की इस त्वरित और जनहितैषी पहल की नगरभर में सराहना हो रही है। नगर पालिका अध्यक्ष सहबीन पनिका, उपाध्यक्ष प्रीति सतीश शर्मा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी पवन साहू, भाजपा मंडल अध्यक्ष रिंकू शर्मा सहित समस्त पार्षदों, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मंत्री के नेतृत्व में नगर की वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान तेजी से हो रहा है। स्थानीय नागरिकों का मानना है कि यदि इसी तरह ठोस प्रयास जारी रहे तो आने वाले समय में बिजुरी को स्थायी रूप से जल संकट से मुक्ति मिल सकेगी।

सांसद निधि से बनेगा सामुदायिक भवन, नर्मदा परिक्रमा यात्रियों को मिलेगा लाभ

अमरकंटक। मध्यप्रदेश के प्रमुख पर्यटन एवं धार्मिक तीर्थ स्थल पवित्र नगरी अमरकंटक के नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 12 में रेवा सामुदायिक भवन निर्माण कार्य का भूमि पूजन विधि-विधान के साथ संपन्न हुआ। यह निर्माण कार्य राज्यसभा सांसद विवेक तंखा द्वारा सांसद निधि से प्रदत्त 10.78 लाख रुपये की लागत से कराया जाएगा।
कार्यक्रम में पुष्पराजगढ़ क्षेत्र के विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को ने मुख्य अतिथि के रूप में भूमि पूजन कर भवन निर्माण की आधारशिला रखी। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती पार्वती सिंह उइके ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर परिषद उपाध्यक्ष रज्जू सिंह नेताम एवं वार्ड क्रमांक 12 की पार्षद श्रीमती निधि जैन उपस्थित रहीं। इस अवसर पर धार्मिक विधि-विधान एवं पूजन-अर्चन के साथ निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में जनपद पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष संतोष पांडे, आदिवासी कांग्रेस जिला अध्यक्ष आशुतोष सिंह मार्को, नगर कांग्रेस अध्यक्ष शितेश सरीवान, पार्षदगण शक्ति पांडे, जोहनलाल चंद्रवंशी, विमला दुबे, उषा सिंह, पूर्व पार्षद श्यामकली परस्ते, विधायक प्रतिनिधि श्यामलाल सेन, युवा कांग्रेस अध्यक्ष वीरू तंबोली, जितेंद्र खांडे, एनएसयूआई अध्यक्ष सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं नागरिक उपस्थित रहे।
मुख्य अतिथि विधायक मार्को ने अपने संबोधन में कहा कि निर्माण कार्य

हनुमान जयंती

बिजुरी में भक्ति और सेवा का संगम– भाजपा मंडल द्वारा आयोजित हनुमान जयंती महोत्सव में उमड़ा जनसैलाब

संकटमोचन मंदिर में की महाआरती, सुंदरकांड पाठ और भंडारे में हुए शामिल दिलीप जायसवाल

विजय मत, अनूपपुर

कोयलांचल नगरी के वार्ड क्रमांक 6 स्थित संकटमोचन हनुमान मंदिर में मंगलवार को भक्ति, शक्ति और सेवा का त्रिवेणी संगम देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी मंडल बिजुरी द्वारा आयोजित भव्य हनुमान जयंती महोत्सव में क्षेत्रीय जनभावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। इस विशेष अवसर पर लोकप्रिय विधायक मध्यप्रदेश शासन के मंत्री दिलीप जायसवाल ने बजरंगबली के चरणों में मत्था टेका और क्षेत्र की सुख-शांति के लिए मंगल कामना की।

भक्तिमय रहा वातावरण

प्रातः 9 बजे से ही मंदिर परिसर सुंदरकांड के सस्वर पाठ से भक्तिमय हो उठा। ढोल-मजीरों की थाप और सुंदरकांड हनुमान चालीसा के जयघोष के बीच क्षेत्र का वातावरण आध्यात्मिक हो गया। दोपहर में जब महाआरती हुई तो मंत्री दिलीप जायसवाल सहित सैकड़ों श्रद्धालुओं ने एक स्वर में पवनपुत्र की स्तुति की।

समरसता का संदेश

दर्शन के पश्चात आयोजित विशाल भंडारे में श्री जायसवाल ने न केवल स्वयं प्रसादी ग्रहण की, बल्कि श्रद्धालुओं के बीच पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। उन्होंने कहा श्री हनुमान जी का जीवन हमें अटूट भक्ति और निस्वार्थ सेवा की सीख देता है। भाजपा मंडल द्वारा आयोजित यह महोत्सव हमारी धार्मिक परंपराओं को सहेजने का एक सराहनीय प्रयास है। कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारी, मातृशक्ति, युवा साथी और गणमान्य नागरिकों की गरिमामयी उपस्थिति रही।

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी उत्तर शहडोल वनमण्डल म.प्र.

फोन नं0 07652-245167 ईमेल- dfotnshahd-mp@gov.in
क्र./व्यय / 758 शहडोल, दिनांक 31/03/ 2026

निविदा विज्ञप्ति

वनमण्डल अंतर्गत विभिन्न वानिकी एवं अद्योसंरचना कार्यों हेतु प्रयोग होने वाली सामग्रियों की आपूर्ती हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	सामग्री का नाम	संत्याकार निधि
01	वानिकी एवं अद्योसंरचना हेतु प्रयोग होने वाली सामग्री	150000

निविदा के संबंध मे समस्त जानकारी ई निविदा क्रमांक 2026_MPFD_495052_1 के माध्यम से प्राप्त करे।

G11073/26

वनमण्डलाधिकारी
उत्तर शहडोल वनमण्डल म.प्र.

न्यूज इन शॉर्ट

गीतकार आनंद बख्शी के गीतों पर आधारित संगीत निशा कल

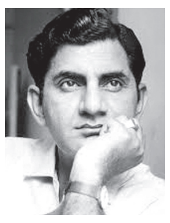

विजय मत, ब्यूरो इन्दौर। सुप्रसिद्ध गीतकार आनंद बख्शी के गीतों पर आधारित संगीत निशा.. ये वक्त न खो जाए.. का आयोजन कल 5 अप्रेल को शाम 6.30 बजे से प्रीतमलाल दुआ सभागृह में आयोजित किया जा रहा है। संस्था संगीत आनंद द्वारा आयोजित हिंदी फिल्मी गीतों के शहंशाह आनंद बख्शी के सदाबहार गीतों पर आधारित इस संगीत संध्या में उनके गीतों को आकृति सोनी, बिजासिनी, वैशाली, विकास, प्रमोद, संजय रजनी पेश करेंगे। सभी संगीत प्रेमियों के लिए निशुल्क खुले इस आयोजन का संचालन डॉ. सुमित्रा जोशी करेंगी।

प्लाट के नाम पर 6 लाख की धोखाधड़ी करने वाले को सात साल की जेल

विजय मत, भोपाल। पंचवटी इनक्लेव एयरपोर्ट रोड भोपाल में प्लाट देने के नाम पर धोखाधड़ी करते हुए फरियादिया से छह लाख रुपए हड़पने के मामले के आरोपी डीआईएल कंपनी के तत्कालीन मैनेजिंग डायरेक्टर रमाकांत विजयवर्गीय को सुनवाई पूरी होने के बाद अपर

सत्र न्यायाधीश स्वंय प्रकाश दुबे की अदालत ने दोषी करार देते हुए 7 साल के कठोर कारावास सहित 2 लाख 25 हजार के जुर्माने की सजा से दण्डित किये जाने की सजा सुनाई है। मामले में फरियादिया की आशा गुप्ता की ओर से एडवोकेट संजय गुप्ता ने पैरवी की। अभियोजन से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी रमाकांत विजयवर्गीय पंचवटी इनक्लेव एयरपोर्ट रोड भोपाल स्थित कॉलोनी में प्लाट बेचने के नाम पर पीड़िता आशा गुप्ता से 6 लाख हड़पकर फरार हो गया था। ठगी होने का एहसास होने पर महिला ने 6 अगस्त 2020 को कोहेफिजा थाने में आरोपी रमाकांत विजयवर्गीय के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। थाना पुलिस ने आरोपी रमाकांत विजयवर्गीय के खिलाफ धारा-409 और 420 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच के बाद जिला अदालत में चालान पेश किया था। गौरतलब है कि आरोपी ने अनेक लोगों को पंचवटी इनक्लेव एयरपोर्ट रोड भोपाल में प्लाट देने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी की है।

ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के नाम पर प्रापर्टी डीलर से लाखों की ठगी

विजय मत, भोपाल। चूनाभट्टी इलाके में ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के नाम पर प्रापर्टी डीलर से 18 लाख से अधिक की ठगी पने के मामले में पुलिस ने उन बैंक खातों को

फ्रीज करवा दिया है। जिन खातों में ठगी की रकम ट्रांसफर की गई थी। सूत्रो के मुताबिक पुलिस ने जब उन नंबरों को ट्रेस किया, जिन नंबरों फोन आते तब तो पता चला कि वह नंबर विदेश के हैं। जालसाज केवल व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से ही बातचीत किया करते थे। पुलिस के मुताबिक चाणक्यपुी में रहने वाले 50 वर्षीय ललित नामदेव प्रापर्टी डीलर का काम करते हैं। जनवरी माह में अपने मोबाइल पर रील देख रहे थे। तभी उनके पास एप आई, जिसमें उन्हें शेयर मार्केट में निवेश करने पर मोटा मुनाफा मिल सकता है। लालच में आकर उन्होंने एप के माध्यम से एक सोशल मीडियाग्रुप में जुड़ गए। जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से शेयर में निवेश करना है। इसके बाद उन्होंने अलग-अलग किस्तों में करीब 18 लाख 55 हजार रुपए निवेश कर दिए। बाद में उन्हें ना तो निवेश की हुई रकम पर कोई प्रॉफिट मिला और ना ही निवेश की हुई रकम वापस मिली।

कॉफी हाउस सहित तीन दुकानों पर चोरों ने बोला धावा

विजय मत, भोपाल। शहर के एमपी नगर थाना इलाके में बेखौफ चोरो ने बोर्ड ऑफिस के करीब स्थित इंडियन कॉफी हाउस सहित तीन दुकानो के ताले चटकाकर 60 हजार की नगदी सहित अन्य सामान चोरी कर लिया। जानकारी के अनुसार रोज की तरह गुरुवार रात 11 बजे इंडियन कॉफी हाउस बंद हुआ था। अगली सुबह करीब 9 बजे जब कर्मचारी रेस्टोरेंट को खोलने पहुंचे तो उसका ताला टूटा मिला। अंदर जाकर चेक करने पर दराज में रखी साठ हजार की नगदी गायब मिली। बाद में पता चला की रेस्टोरेंट के पड़ोस में स्थित दो अन्य दुकानों के भी बदमाशों ने ताले चटका दिए। सूचना मिलने पर पहुचीं पुलिस आरोपियों का सुराग जुटाने के लिये घटना स्थल के आस पास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है।

कांग्रेस विधायक राजेन्द्र भारती की विधानसभा सदस्यता समाप्त होने के बाद शुरू हुआ आरोप-प्रत्यारोप का दौर

सदस्यता समाप्ति की कार्यवाही नियमों और कानून के तहत : स्पीकर तोमर

विजय मत, ब्यूरो ग्वालियर

कांग्रेस विधायक राजेन्द्र भारती की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि विधानसभा द्वारा जो भी कार्यवाही की गई है वह नियमों और कानून के तहत की गई है। विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि दतिया के विधायक राजेंद्र भारती के मामले में न्यायालय ने फैसला दिया और उसमें उनको दोषी सिद्ध पाया जिसके तहत 3 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई,स्वाभाविक रूप से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की 151 की धारा 8(3) में

यह प्रावधान है,2 वर्ष या उससे अधिक की सजा किसी जनप्रतिनिधि को होती है तो वह अपने आप में अयोग्य हो जाता है,इसलिए न्यायालय का निर्णय आया तो हमको सूचना मिली,साथ ही एक नागरिक ने भी कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए उसका पालन किया जाए यह भी विधानसभा में आग्रह किया,उसके बाद हम सब लोगों ने अपने वकीलों से मशवरा किया और एडवोकेट जनरल से भी राय ली गई और उस राय के मुताबिक जो कानून में प्रावधान था उसके हिसाब से निर्णय किया गया,कोर्ट के निर्णय के परिपेक्ष में राजेंद्र भारती जी की जो सदस्यता थी वह अयोग्य घोषित हो गई है,इसकी सूचना चुनाव आयोग और संबंधित सरकारी पक्ष है उन सबको वह सूचना कल रात में दे दी गई है, इससे पूर्व में भी ऐसे उदाहरण हमारे सामने है,मध्य प्रदेश विधानसभा की विधायक आशा देवी के मामले में भी इस प्रकार का निर्णय आया था और सजा के आधार पर उनकी भी सदस्यता गई थी,2019 में प्रहलाद लोधी विधायक थे उनके मामले में भी इसी प्रकार का निर्णय आया था और उन्हें भी अयोग्य घोषित किया गया था,मैं समझता हूं कि जो कार्यवाही विधानसभा में हुई है वह विधि अनुसार है और उस मामले में विधानसभा जो करना था वह काम पूरा किया है। कोर्ट द्वारा 30 दिन के समय दिए जाने के वाबजूद जल्दबाजी में कार्रवाई किये जाने के कॉंग्रेस के आरोपो पर उन्होंने कहा कि सामान्य तौर पर मैं किसी आरोप प्रत्यारोप का जवाब नहीं देना चाहता हूं, विधानसभा और विधानसभा अध्यक्ष यह सामान्य तौर पर अलग प्रकार के पद हैं इनमें दलगत भावना से ऊपर उठकर ही सारा काम किया जाता है मैं इतने दिन से अध्यक्ष हूं सभी पक्षों के लोगों से आप बात कर सकते हैं मेरी कोशिश रहती है जो विधि अनुसार है जो नियम प्रक्रिया के अनुसार है वही काम किया जाए जवाब देने के लिए बहुत सारे लोग हैं वह आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना है मैंने पूर्व में भी बताया है भाजपा की जो सदस्य थे उनकी भी सदस्यता गई थी इसी कानून के अंतर्गत गई थी और इसी विधानसभा ने निर्णय किया था।

न्यायालय का जो आदेश होगा वह सर्वोपरि होगा

विधानसभा में राजेंद्र भारती मामले में शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग करने वाले व्यक्ति से जुड़ी जानकारी के सवाल पर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मिस्टर गौतम है, उन्होंने कोर्ट के सभी केसों का हवाला देकर शिकायत की थी, स्वाभाविक रूप से किसी भी नागरिक अधिकार होता है, वह कार्रवाई की मांग कर सकता है, मिस्टर गौतम ने भी उसी आधार पर शिकायत की थी, अगली प्रक्रिया हमारी तरफ से पूर्ण है अब माननीय न्यायालय इस मामले में कोई आगे आदेश देता है न्यायालय का जो आदेश होगा वह सर्वोपरि होगा।

विधानसभा सभी की होती है सब लोग आ सकते हैं

मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के विधानसभा में विधायक ना होते हुए भी पहुंचने के मामले पर उन्होंने कहा कि हमारे प्रमुख सचिव बाहर थे वह रात में नौ बजे के आसपास विधानसभा आए थे इसलिए वह अपनी कार्रवाई करने के लिए और कुछ अन्य कामों की बैठक के लिए वहां पहुंचे हुए थे, स्वाभाविक रूप से विधानसभा सभी की होती है सब लोग आ सकते हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि जो कुछ हुआ है वह सब माननीय न्यायालय के निर्देश अनुसार हुआ है,माननीय न्यायालय का आदेश सभी संस्थाओं के लिए सर्वोपरि होता है आगे कोई आदेश आएगा तो उस पर कानूनी मशवरा करके आगे बढ़ा जाएगा।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किया दावा

राजेंद्र भारती और मुकेश मल्होत्रा फिर बनेंगे विधायक: पटवारी

विजय मत, भोपाल

दतिया विधानसभा के कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता को लेकर सियासत जारी है। मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मुकेश मल्होत्रा और राजेंद्र भारती फिर विधायक बनेंगे। मैंने पहुंचकर रात में विधानसभा खोलने का कारण पूछा, विधानसभा प्रमुख सचिव ने कहा था रात में विधानसभा खोलने की कोई सोच नहीं है। उन्होंने रुटिन का काम बताया, सुबह पता चला विधायक राजेंद्र भारती की सदस्ता निरस्त की।

उन्होंने कहा कि हम सदन में नहीं गए, विधानसभा परिसर में गए थे। नरोत्तम मिश्रा पर पेड न्यूज का मामला इसी विधानसभा का है। निर्मला सप्रे पर विधानसभा ने कोई निर्णय नहीं लिया। बीजेपी अलोकतांत्रिक का कैंसर बन गई है। तीसरी सीट से राज्यसभा 500-700 प्रतिशत कांग्रेस प्रत्याशी ही जाएंगे। राज्यसभा चुनाव फैक्टर के लिए बीजेपी नंबर कम करने में लगी है लेकिन बीजेपी कामयाब नहीं होगी।

ये संकट था नहीं, पैदा किया गया

गेंहू खरीदी की तारीख बढ़ने पर बोले कि 10 करोड़ बारदानों की आवश्यकता थी लेकिन ढाई करोड़ का ही ऑर्डर किया। बारदाने नहीं होने से गेंहू नहीं खरीद रहे, ये संकट था नहीं, पैदा किया गया है। जूट बारदान के लिए आवेदन ही नहीं किया। खरीदी होती तो ओला-पाला से फसलें प्रभावित नहीं होतीं, एक्सपर्ट-इम्पोर्ट नीति भी सही नहीं है। खरीदी की तारीख बढ़ी तो सोसायटी में पैसे जमा करने की तारीख क्यों नहीं बढ़ाई।

कृषि मंत्री के बंगले का करेंगे घेराव

जीतू पटवारी ने कहा कि किसानों के मामले को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले का घेराव करेंगे। भोपाल स्थित बंगले का घेराव होगा। एक दिन का उपवास करेंगे, मंडियों में भी आंदोलन करेंगे।

दादाजी धाम मंदिर में गलंतिका जलधारा से 24 घंटे अभिषेक प्रारंभ

विजय मत, भोपाल। वैशाख मास की शुरुआत 3 अप्रैल 2026 से हो गई है। इस पावन अवसर पर दादाजी धाम मंदिर, रायसेन रोड, पटेल नगर में भगवान शिव के शिवलिंग पर गलंतिका जलधारा स्थापित कर 24 घंटे निरंतर अभिषेक प्रारंभ किया गया है। पंडित राजेंद्र पलिया द्वारा विधि-विधान से पूजन कर एवं भक्तों की उपस्थिति में गलंतिका स्थापित की गई। विशेष कलश से एक-एक बूंद जल निरंतर शिवलिंग पर गिरकर भक्तों की श्रद्धा एवं भक्ति का प्रतीक बन रही है। ट्रस्ट के अध्यक्ष शिवरतन नामदेव ने बताया कि धार्मिक मान्यता के अनुसार यह जलधारा भगवान शिव को शीतलता प्रदान कर अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है तथा इससे पापों का क्षय, कष्टों का निवारण एवं सुख-शांति की प्राप्ति होती है।

गुड-फ्राइडे पर क्रूस की दु :खमयी यात्रा का सजीव मंचन

"मसीह क्रूस उठा के चला, जमी रो उठी, आसमा रो उठा"

विजय मत, ब्यूरो जबलपुर

लड़खड़ाते कदम... लहुलूहान बदन... सिर पर काँटों का ताज एवं भारी क्रूस के बोझ को लेकर चलते प्रभु येसु को देखकर शहर की मुख्य सड़कों पर चल रहे राहगीर थम गये। कौतूहलवश वे इस दर्दनाक एवं दुःखमयी यात्रा के दृश्यों को देखकर आंसू बहा रहे थे। अवसर था गुड-फ्राइडे (पुण्य शुक्रवार) के पावन अवसर पर बालक येसु के तीर्थ स्थल, होली ट्रिनीटी चर्च द्वारा निकाली जा रही क्रूस की दुःखमयी यात्रा का। जिसमें नगर के विभिन्न चर्चों के ख्रीस्तीय कलाकार प्रभु येसु के दुःखभोग के दृश्यों को सजीव मंचन कर रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे दो हजार वर्षों पूर्व येरुषलेम की सड़कों पर मुक्तिदाता येसु मसीह को क्रूस देकर जो यातनायें दी गई थी, वो हजारों आँखों के सामने सजीव हो उठीं। संस्कारधानी के संपूर्ण ख्रीस्तीय समाज के साथ-साथ अन्य धर्मावलंबी भाई-बहिनों की आँखें भी येसु को क्रूस लिये देखकर नम हो गई। इस क्रूस यात्रा के दौरान दर्द भरे धार्मिक गीतों- ''प्यारे येसु अब तो गुनाहों से तौबा'', ''जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है'', ''जमी रो उठी आसमाँ रो उठा हमारा मसीह क्रूस उठा के चला'', ''काँटें हो रहा पर कभी चलते ही जायें हम''... गाते हुये अश्रुपूर्ण नेत्रों से विश्वासियों की सहभागिता देखने को मिली। इस क्रस की दुःखमयी यात्रा में गेतसेमनी बाग में येसु द्वारा प्रार्थना के दृष्य से लेकर कैफस के महल में पेशी, येसु को रोमी राज्यपाल पिलातुस द्वारा प्राणदंड की सजा, कांधों पर क्रूस लाद कर कलवारी पहाड़ के मार्ग पर लड़खड़ाते हुये चलते येसु राह में धर्मी स्त्री वेरोनिका एवं येरुशलेम की स्त्रियों से मिलते हैं, जहाँ स्त्रियाँ येसु को प्राण पीड़ा में देखकर रोती-बिलखती है।

सहकारी समिति के कर्मचारियों ने किसानों से वसूली की 41 लाख की रकम हड़पी

विजय मत, भोपाल। ईंटखेड़ी थाना पुलिस ने सहकारी समिति के तीन ऐसे शातिर कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिन्होनें किसानों से हुई वसूली करीब 41 लाख 94 हजार की रकम हड़प कर चंपत हो गए। सहकारी समिति के प्रशासक की शिकायत पर पुलिस ने जॉच के बाद तीन कर्मचारियों के खिलाफ मामला कायम कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम रायपुर के सहकारी समिति के प्रशासक रामचरण सिलावट ने लिखित शिकायसती आवेदन देते हुए बताया कि उनकी समिति में काम करने वाले तीन कर्मचारी मनोज कुमार जाटव, नरेंद्र और मुकेश किसानों से लोन की ईएमआई वसूली का काम देखते हैं। तीनों ने बीते काफी समय में किसानों से करीब 41 लाख 94 हजार की वसूली तो की लेकिन इस रकम को आरोपियों ने सोसायटी में जमा नहीं करते हुए खुद हड़प लिया। जानकारी लगने पर समिति ने तीनो कर्मचारियों को कई बार नोटिस देकर रकम जमा कराने को कहा लेकिन आरोपियों ने पैसे जमा नहीं किए। शिकायत की जॉच के आधार पर पुलिस ने तीनो आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।

चुंगी क्षतिपूर्ति से चुकता किया निकायों का बिजली बिल

नगरीय निकायों की वित्तीय हालत खराब बिजली का बिल तक नहीं चुका पा रहे

विजय मत, भोपाल

प्रदेश के नगरीय निकायों की वित्तीय हालत बेहद खराब है। हालात ऐसे हैं कि अधिकतर निकाय बिजली का बिल तक नहीं चुका पा रहे हैं। हालही में सागर के शाहगढ़ नगर पालिका कार्यालय का बिजली कनेक्शन काट दिया गया। इस हाल में नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश के 217 नगरीय निकायों के बिजली बिलों का एकमुश्त भुगतान किया है। यह रकम

106 करोड़ रुपये की थी जिसकी वजह से बिजली कंपनियों पर दबाव बढ़ा था। नगरीय निकायों पर 25 मार्च तक बकाया बिजली देयकों का निपटारा करने के लिए माह मार्च 2026 की चुंगी क्षतिपूर्ति की 106 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया है। इसमें सबसे अधिक इंदौर नगर निगम का 26 करोड़ और दूसरे नंबर पर भोपाल नगर निगम के बिजली बिल की बकाया 13 करोड़ रुपये राशि का भुगतान किया गया है। इसके अलावा ग्वालियर की 9.34 करोड़, जबलपुर की 6.22 करोड़ रुपये की राशि भी विद्युत कंपनियों के खाते में ट्रांसफर कर दी है। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 25 मार्च 2026 की स्थिति में निकायों पर भारी बकाया दिख रहा था। इस वित्तीय भार को उठाने में भोपाल, इंदौर जैसे संसाधनों वाले नगर निगमों ने हाथ खड़े कर लिए थे। इस वित्तीय बोझ को कम करने के लिए विभाग ने निकायों के हिस्से की राशि काटकर तीन प्रमुख विद्युत वितरण कंपनियों को भुगतान किया है। विंध्याचल कोषालय के माध्यम से मध्य क्षेत्र कंपनी को 40.75 करोड़, पूर्व क्षेत्र कंपनी को 24.55 करोड़ और पश्चिम क्षेत्र कंपनी को 41.29 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। नगरीय प्राशासन एवं विकास संचालनालय ने सख्त निर्देश दिए हैं कि आवंटित राशि का समायोजन केवल उन्हीं कनेक्शनों के विरुद्ध किया जाए, जिनमें बकाया राशि अधिक है।

एक और फार्म हाउस पर पुलिस की रेड पिस्टल कारतूस सहित एक गिरफ्तार

विजय मत, ब्यूरो इंदौर

विगत दिनों एक आईएएस के फार्म हाउस पर पकड़ाएं बड़े जुएं के मामले के बाद पुलिस सतत् फार्म हाउस पर निगरानी रख कार्रवाई कर रही है जिसका चलते कल फिर एक फार्म हाउस पर देर रात तक अवैध रूप से चल रही शराब पार्टी पर छापामार कार्रवाई की थी वहीं आज फिर पुलिस ने एक फार्म हाउस पर छापामार कार्रवाई करते अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। मामला खुडैल थाना क्षेत्र का है। डीएसपी उमाकांत चौधरी के अनुसार कल देर रात ग्राम गढ़ी स्थित अनुभूति फार्म हाउस में संदिग्ध गतिविधियां की सूचना मिलने के बाद रात करीब 1:15 बजे थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची तलाशी शुरू की तो पाया कि फार्म हाउस संचालक अर्चना सिंह ने वहां ठहरे लोगों की सूचना थाने में नहीं दी गई थी। साथ ही आने-जाने वाले व्यक्तियों की एंट्री के लिए भी कोई विजिटिंग रजिस्टर नहीं रखा गया था। इस दौरान पुलिस ने वहां मौजूद सुरजभान सिंह पिता प्रेमपाल सिंह राघव राजपुत उम्र अड़तीस साल निवासी किराडी सुलेमान नगर थाना अमन विहार दिल्ली को पकड़ा और उसकी स्कॉर्पियो कार नंबर डीएल-4सी-बीडी3562 की तलाशी ली तो उसमें से एक अवैध पिस्टल और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए वहीं पुलिस टीम को सुरजभान फार्म हाउस में शराब के नशे में मिला पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर फार्म हाउस संचालक अर्चना सिंह पर भी नियमों के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई की है।

विजय मत एंकर — मैहर में मां शारदा लोक परियोजना को मिली गति, श्रद्धालुओं को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

देवी शक्ति पीठ मां शारदा लोक से बदलेगा विंध्य का धार्मिक स्वरूप

विजय मत, ब्यूरो मैहर

विंध्य क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक केंद्र मां शारदा देवी शक्तिपीठ के विकास के लिए प्रस्तावित 'मां शारदा लोक' परियोजना अब तेजी से आगे बढ़ रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत त्रिकूट पर्वत और आसपास के पूरे क्षेत्र को सुव्यवस्थित, आकर्षक और श्रद्धालु-अनुकूल बनाया जाएगा। इसी सिलसिले में रीवा संभाग के कमिश्नर बीएस जामोद और पुलिस महानिरीक्षक गौरव राजपूत ने मैहर पहुंचकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में कंसल्टेंसी एजेंसी द्वारा परियोजना का विस्तृत मास्टर प्लान प्रस्तुत किया गया, जिसमें पूरे तीर्थ क्षेत्र को तीन प्रमुख जोनों में विकसित करने की योजना है। इनमें घंटाघर से मंदिर मार्ग, मंदिर परिसर और मेला क्षेत्र शामिल हैं। इस योजना का उद्देश्य भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा को बेहतर बनाना है।

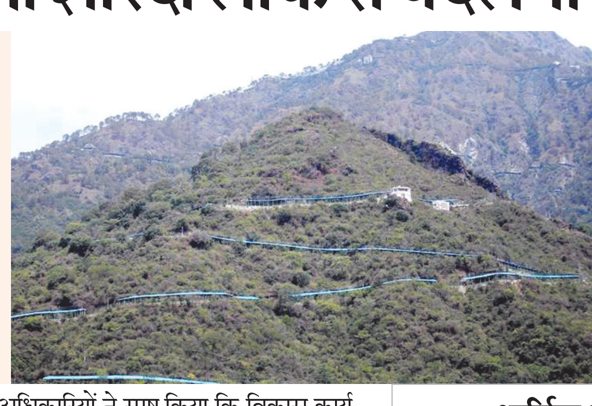

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि विकास कार्य के दौरान त्रिकूट पर्वत की प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व को सुरक्षित रखा जाएगा। साथ ही सुरक्षा, सुगम दर्शन और आधुनिक व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि आने वाले समय में बढ़ने वाली श्रद्धालुओं की संख्या को बेहतर तरीके से संभाला जा सके।

इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधा विकास पर रहेगा जोर

परियोजना के तहत आधारभूत सुविधाओं को भी मजबूत किया जाएगा। पुलघटा क्षेत्र में बड़ी पार्किंग, रोपवे की क्षमता बढ़ाने और ऑडिटोरियम निर्माण की योजना बनाई गई है। अधिकारियों ने 15 मई तक निविदा प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू करने का लक्ष्य तय किया है। इसके अलावा सुरक्षा, यातायात और भीड़ नियंत्रण के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए यह परियोजना मैहर को देश के प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

धार्मिक और सांस्कृतिक सुविधाओं का होगा विस्तार

मां शारदा लोक परियोजना के तहत तीर्थ क्षेत्र में कई नई सुविधाओं का निर्माण प्रस्तावित है। इसमें मुंडन संस्कार भवन, यज्ञशाला, सांस्कृतिक क्षेत्र, परिक्रमा पथ और भजन संध्या स्थल विकसित किए जाएंगे। साथ ही नवग्रह वाटिका का निर्माण भी किया जाएगा, जहां श्रद्धालु धार्मिक अनुष्ठान कर सकेंगे। इन सभी सुविधाओं का उद्देश्य तीर्थ क्षेत्र को आधुनिक स्वरूप देने के साथ उसकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करना है। इससे श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिलेगा और धार्मिक आयोजन भी व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सकेंगे।

एमटीए का काम बंद हड़ताल का ऐलान, 6 अप्रैल को थम सकती हैं मेडिकल सर्विस

विजय मत, भोपाल

राजधानी के गांधी चिकित्सा महाविद्यालय (जीएमसी) में सीधी भर्ती के विरोध में मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन यानि एमटीए का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा। गुरुवार को चिकित्सकों ने एक घंटे का कार्य बहिष्कार कर प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि जल्द फैसला नहीं लिया गया तो सोमवार से आंदोलन और उग्र होगा। इस दौरान अस्पतालों में मरीजों के इलाज की व्यवस्थाएं भी चरमरा सकती हैं। एमटीए के आह्वान पर हमीदिया अस्पताल के ब्लॉक-2 पोर्च पर दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक चिकित्सा शिक्षकों ने काम का बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ओपीडी से लेकर अकादमिक गतिविधियां प्रभावित रहीं। विभागाध्यक्षों से लेकर मेडिकल ऑफिसर्स तक बड़ी संख्या में चिकित्सक धरने में शामिल हुए।

आंदोलन में शामिल चिकित्सकों ने आरोप लगाया है कि दो दिनों से चल रहे विरोध और पेन-डाउन स्ट्राइक के बावजूद गांधी मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने विवादित विज्ञप्ति को निरस्त करने के संबंध में कोई पहल नहीं की है। एमटीए पदाधिकारियों का कहना है कि जब ग्वालियर हाईकोर्ट समान मामले में सीधी भर्ती को खारिज कर चुका है, तब भी जीएमसी भोपाल प्रशासन इस मुद्दे पर गंभीरता नहीं दिखा रहा है। एमटीए महासचिव डॉ. अविनाश ठाकुर ने कहा कि यह आंदोलन चिकित्सा शिक्षकों के अधिकारों और सम्मान से जुड़ा है।

आज दो घंटे का बहिष्कार

कॉलेज प्रबंधन ने यदि बात नहीं मानी तो संघ ने आंदोलन के अगले चरण की भी घोषणा कर दी है। डॉ. राकेश मालवीय ने बताया कि 4 अप्रैल को दो घंटे का कार्य बहिष्कार किया जाएगा और चिकित्सक काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराएंगे। यदि इसके बाद भी विवादित विज्ञप्ति निरस्त नहीं की गई तो 6 अप्रैल से अनिश्चितकालीन क्रमिक कार्य बंद आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिससे अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यापक असर पड़ सकता है।

संस्थापक
श्री रामसिपाही शुक्ल

विवाह संस्था और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच नई खाई

मोहन योगी

आधुनिकता के संक्रमणकालीन दौर में सबसे अधिक यदि कोई संस्था प्रश्नों के घेरे में है, तो वह विवाह और रिश्तों की पारंपरिक अवधारणा है। बदलती जीवनशैली, आर्थिक आत्मनिर्भरता, तकनीक, वैश्वीकरण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बढ़ती चेतना ने रिश्तों की परिभाषा, अपेक्षाएँ और संरचना-सब कुछ बदल दिया है। यही कारण है कि आज रिश्तों से जुड़े प्रश्न केवल सामाजिक विमर्श का विषय नहीं रहे, बल्कि अदालतों तक पहुँच रहे हैं। हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दो फैसलों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विवाह संस्था के बीच उत्पन्न हो रही नाजुक खाई को उजागर किया है। एक निर्णय में न्यायालय ने कहा कि वयस्कों के बीच आपसी सहमति से बना लिव-इन रिलेशनशिप, भले ही एक साथी विवाहित हो, अपराध नहीं है; वहीं दूसरे मामले में न्यायालय ने ऐसे ही एक जोड़े को संरक्षण देने से इनकार कर दिया और कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर पति या पत्नी के कानूनी अधिकारों को कमजोर नहीं किया जा सकता। यह विरोधाभास वास्तव में न्यायिक असंगति से अधिक एक कानूनी रिक्तता और सामाजिक संक्रमण का संकेत है। वास्तव में एक हकीकत यह भी है कि भारतीय समाज में वैवाहिक अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने वाले एक प्रभावी ढांचे की लंबे समय से आवश्यकता महसूस की जाती रही है। हमें मौजूदा परिदृश्य में यह बात स्वीकार करनी होगी कि यद्यपि विवाह संस्था संरक्षण की हकदार है, फिर भी पुरुष या स्त्री की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अनिश्चित काल तक इसके अधीन बंधक बनाकर नहीं रखा जा सकता है।

आज रिश्तों से जुड़े प्रश्न केवल सामाजिक विमर्श का विषय नहीं रहे, बल्कि अदालतों तक पहुँच रहे हैं। हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दो फैसलों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विवाह संस्था के बीच उत्पन्न हो रही नाजुक खाई को उजागर किया है। एक निर्णय में न्यायालय ने कहा कि वयस्कों के बीच आपसी सहमति से बना लिव-इन रिलेशनशिप, भले ही एक साथी विवाहित हो, अपराध नहीं है; वहीं दूसरे मामले में न्यायालय ने ऐसे ही एक जोड़े को संरक्षण देने से इनकार कर दिया और कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर पति या प%ी के कानूनी अधिकारों को कमजोर नहीं किया जा सकता। यह विरोधाभास वास्तव में न्यायिक असंगति से अधिक एक कानूनी रिक्तता और सामाजिक संर मण का संकेत है।

निश्चित ही भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है और इसी के दायरे में न्यायालयों ने समय-समय पर लिव-इन रिलेशनशिप को अपराध की श्रेणी से बाहर माना है। लेकिन दूसरी ओर, भारतीय कानून विवाह को एक कानूनी और सामाजिक संस्था के रूप में सर्वोच्च प्राथमिकता देता है, जिसमें अधिकार और दायित्व दोनों शामिल हैं। यही वह बिंदु है जहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता और वैवाहिक अधिकारों के बीच टकराव उत्पन्न होता है। न्यायालय लिव-इन संबंधों को अपराध नहीं मानता, परंतु उनके सभी परिणामों को वैध मानने में संकोच करता है। यह स्थिति न केवल कानूनी भ्रम उत्पन्न करती है, बल्कि सामाजिक असुरक्षा भी पैदा करती है। वास्तव में समस्या न्यायिक निर्णयों की नहीं, बल्कि स्पष्ट विधायी ढाँचे की कमी की है। यदि व्यापक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारतीय समाज इस समय एक बड़े संक्रमणकाल से गुजर रहा है। एक ओर सदियों से स्थापित पारंपरिक जीवन मूल्य हैं, जिनमें विवाह केवल एक अनुबंध नहीं बल्कि एक संस्कार, सामाजिक स्वीकृति और पारिवारिक व्यवस्था का आधार है; दूसरी ओर आधुनिक जीवन की वास्तविकता है, जहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता, आत्म-विकास, करियर, आर्थिक स्वायत्तता और व्यक्तिगत संतुष्टि को भी समान महत्व दिया जा रहा है। विशेष रूप से महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता ने रिश्तों की शक्ति-संतुलन व्यवस्था को बदल दिया है। अब रिश्ते केवल सामाजिक दबाव से नहीं, बल्कि आपसी समझ और संतुष्टि के

आधार पर टिके रहते हैं। परिणामस्वरूप, रिश्तों की स्थायित्व की अवधारणा बदल रही है और प्रतिबद्धता अब आजीवन वचन से अधिक एक निरंतर पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया बनती जा रही है।

पिछली पीढ़ियों में विवाह जीवन का अनिवार्य चरण माना जाता था। हमारे माता-पिता और दादा-दादी के लिए विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो परिवारों का संबंध था और जीवन भर साथ निभाना ही उसका लक्ष्य था। लेकिन आधुनिक पीढ़ी रिश्तों को अलग दृष्टि से देख रही है। आज के युवा पहले शिक्षा, करियर और आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता देते हैं, उसके बाद रिश्तों के बारे में निर्णय लेते हैं। कुछ लोग विवाह से पहले साथ रहने का विकल्प चुनते हैं, कुछ रिश्तों को नाम देने से भी बचते हैं और कुछ लोग विवाह के बजाय साझेदारी को अधिक उपयुक्त मानते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि आधुनिक पीढ़ी रिश्तों को महत्व नहीं देती, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वे रिश्तों में स्वतंत्रता, सम्मान, संवाद और समानता को अधिक महत्व देते हैं। रिश्तों में सबसे बड़ा परिवर्तन लिंग भूमिकाओं के बदलाव से भी आया है। पहले पुरुष कमाने वाला और महिला घर संभालने वाली मानी जाती थी, लेकिन आज दोनों काम करते हैं, दोनों निर्णय लेते हैं और दोनों भावनात्मक सहयोग चाहते हैं। आधुनिक रिश्तों में समानता, खुलकर संवाद और साझा जिम्मेदारियों पर जोर है। हालांकि पुरुष और महिलाओं की अपेक्षाएँ पूरी तरह समान नहीं होतीं-अक्सर महिलाएँ भावनात्मक सहयोग और संवाद को अधिक महत्व देती हैं, जबकि पुरुष स्वतंत्रता और बौद्धिक जुड़ाव को महत्वपूर्ण मानते हैं लेकिन इन अंतरों को समझकर ही मजबूत रिश्ते बनाए जा सकते हैं।

आज आत्म-प्रेम और आत्म-देखभाल को स्वार्थ नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन का आधार माना जाने लगा है। तकनीक और सोशल मीडिया ने भी रिश्तों की प्रकृति को गहराई से प्रभावित किया है। सोशल मीडिया ने लोगों को जोड़ने का काम किया है, लेकिन इसके साथ तुलना की संस्कृति भी बढ़ी है। अब लोग अपने रिश्तों की तुलना दूसरों की ऑनलाइन तस्वीरों और पोस्ट से करने लगे हैं, जिससे असंतोष व्यापत है।

(यह लेखक के निजी विचार हैं) -साभार

ईरान का भीषण प्रहार और इज़रायल की अग्निपरीक्षा

आज मध्य-पूर्व के तपते और बारूद की गंध से भरे रेगिस्तान में इतिहास की सबसे खतरनाक पटकथा लिखी जा रही है और दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ अमेरिका जैसी महाशक्ति की हेकड़ी ईरान के फौलादी इरादों के सामने पस्त पड़ती दिखाई दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो व्हाइट हाउस की कुर्सी संभालते ही ईरान को पत्थर युग में भेजने की गर्जना कर रहे थे, आज उसी ईरान की अभूतपूर्व सैन्य दृढ़ता और अचूक मिसाइल तकनीक के सामने खुद को बुरी तरह फंसा हुआ पा रहे हैं। ट्रंप का हालिया और चौंकाने वाला बयान, जिसमें उन्होंने अगले 2 से 3 हफ्तों के भीतर ईरान से अपनी सेना को बाहर निकालने की बात कही है, दरअसल कोई सोची-समझी कूटनीतिक जीत नहीं बल्कि एक हारी हुई बाजी से सुरक्षित निकलने की छटपटाहट है क्योंकि अमेरिका की वैश्विक दादागिरी अब ईरान के आत्मसम्मान और उसकी मज़बूत सैन्य घेराबंदी के सामने धराशायी हो चुकी है।

ट्रंप जो खुद को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ डील मेकर कहते थे, आज ईरान की शर्तों के सामने बेबस और लाचार नज़र आ रहे हैं और उनकी शांति की बात दरअसल उनकी अपनी सैन्य विफलता और रणनीतिक हार को छिपाने का एक पारदर्शी पर्दा मात्र है।वे भली-भांति जानते हैं कि अगर वे अब इस युद्ध के मैदान से बाहर नहीं निकले, तो अमेरिका को एक ऐसे क्षेत्रीय महायुद्ध का सामना करना पड़ेगा जिसकी तबाही की आंच सीधे वाशिंगटन की दहलीज तक पहुँचेगी, क्योंकि ईरान ने साफ़ कर दिया है कि मध्य-पूर्व अब अमेरिका की जागीर नहीं है। ईरान का पक्ष आज इस संघर्ष में एक अजेय विजेता की तरह उभरा है जिसने पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि वह अब केवल रक्षात्मक मुद्रा में नहीं रहेगा बल्कि आक्रामक रक्षा की नीति अपनाते हुए दुश्मन को उसके घर में घुसकर तबाह करेगा। हाल ही में तेल अवीव की अभेद्य कही जाने वाली सुरक्षा दीवारों को भेदती ईरानी मिसाइलों और जॉर्डन स्थित अमेरिकी अड्डों पर हुए अचूक हमलों ने यह साबित कर दिया है कि ईरान की सैन्य शक्ति को कम आंकना ट्रंप की सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल थी।

सूचना
सम्पादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित लेख-आलेख एवं विचार लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं। अतः यह जरूरी नहीं है कि विजय मत समूह उपरोक्त लेख या विचारों से सहमत हो। किसी लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही जिम्मेदार हैं।

निरंतर सीखना, क्षमता-आधारित शासन और कर्मयोगी दृष्टि

विनोद सिंह

बदलते वैश्विक परिदृश्य, तीव्र तकनीकी विकास और नागरिक अपेक्षाओं के विस्तार के इस दौर में शासन की प्रकृति भी तेजी से परिवर्तित हो रही है।ऐसे समय में मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत प्रारंभ 'कर्मयोगी साधना सप्ताह' केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के व्यापक रूपांतरण का सशक्त संकेत है। यह पहल नागरिक देवो भव÷ की भावना को केंद्र में रखते हुए सेवा, संवेदना और दक्षता के नए मानक स्थापित करती है–जो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ÷विकसित भारत 2047÷ के स्वप्न से जुड़ी हुई है।नई दिल्ली स्थित डॉ. आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित यह सप्ताह मिशन कर्मयोगी के पाँच वर्ष पूर्ण होने का भी प्रतीक है।यह वह पड़ाव है जहाँ उपलब्धियों का मूल्यांकन करते हुए भविष्य की दिशा तय की जा रही है।इस पहल का उद्देश्य केवल कौशल विकास नहीं, बल्कि एक ऐसी सिविल सेवा का निर्माण करना है,जो सक्षम, उत्तरदायी,पारदर्शी और पूर्णतः नागरिक-केंद्रित हो।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा परिकल्पित विकसित भारत 2047 केवल आर्थिक प्रगति का लक्ष्य नहीं, बल्कि एक समग्र राष्टीय दृष्टि है।यह एक ऐसे भारत की कल्पना करता है जो आत्मनिर्भर,समावेशी, तकनीकी रूप से अग्रणी और सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण हो। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि शासन व्यवस्था भी उसी अनुरूप विकसित हो - जहाँ निर्णय त्वरित हों, सेवाएँ सुलभ हों और नागरिकों का विश्वास सर्वोपरि हो।इसी संदर्भ में प्रधान मंत्री के प्रमुख सचिव डॉ. पी. के. मिश्रा का यह कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भविष्य की सिविल सेवा के लिए निरंतर सीखना अनिवार्य है।अब प्रशिक्षण एक बार का औपचारिक चरण नहीं, बल्कि एक सतत प्रक्रिया बन चुका है-जहाँ अधिकारी ÷कहीं भी,कभी भी सीख सकते हैं। iGOT जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म इस परिवर्तन को गति दे रहे हैं,जो लाखों कर्मियों को ज्ञान और कौशल से जोड़ रहे हैं।डॉ. मिश्रा ने शासन के नियम- आधारित ढाँचे से भूमिका-आधारित मॉडल की ओर संक्रमण को भी रेखांकित किया।यह बदलाव विकसित भारत की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रशासन को अधिक लचीला,परिणामोन्मुख और नवाचार-प्रधान बनाता है। अब केवल नियमों के पालनकर्ता नहीं, बल्कि परिवर्तन के वाहक और समाधाना बन रहे हैं।

(यह लेखक के निजी विचार हैं) -साभार

अब तक युद्ध कोई नहीं जाती

संजय गोस्वामी

तेहरान ने मरी हुई लड़कियों की फ़ोटो जारी की हैं। उनके दुखी माता-पिता के वीडियो और फ़ोटो मीडिया और सोशल मीडिया पर शेयर किए गए, लेकिन हममें से कितने लोगों ने उन्हें देखने की परवाह की, ईरान पर अमेरिका-इज़राइल की बमबारी में एक महीने से ज़्यादा समय से, ईरान के शहर मिनाब में 170 से ज़्यादा लड़कियों और टीचरों के अलावा, कई लोग मारे गए हैं। 24 मार्च को, दर्जनों औरतें रोम की सड़कों पर हाथ में हाथ डाले, नंगे पैर मार्च कर रही थीं। ये गाज़ा और इज़राइल की माँएँ थीं। उनके बच्चे या रिश्तेदार हमास की हिंसा और इज़राइल द्वारा लिए गए बदले के शिकार हुए थे। उनका मैसेज ज़ोरदार और साफ़ था इज़राइल और गाज़ा दोनों के रहने वाले खुद को आदम और हव्वा की औलाद मानते हैं, और उन्हें बस शांति चाहिए। यह मार्च उन लोगों के लिए एक सबक था जो सोचते हैं कि हर इज़राइली गाज़ा को जला देना चाहता है।

अमेरिका- इज़राइल और ईरान युद्ध युद्ध जिस पर दुनिया भर के मीडिया का ध्यान है। सारे चैनल युद्ध पर और खबर जो दिखाई जा रही है उससे शांति नष्ट हो गई है – युद्ध ने इंसानियत के मतलब पर हज़ारों बातचीत शुरू कर दी होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मीडिया ने इसे नज़रअंदाज़ करना चुना, जिससे हमें हैरानी हुई कि क्या हमने अपने आस-पास एक अंधा और असंवेदनशील सोशल बबल बना लिया है। ईरान पर अमेरिका-इज़राइल की बमबारी में एक महीने से ज़्यादा समय से, ईरान के शहर मिनाब में 170 से ज़्यादा लड़कियों और टीचरों के अलावा, कई लोग मारे गए हैं। तेहरान ने मरी हुई लड़कियों की फ़ोटो जारी की हैं। उनके दुखी माता-पिता के वीडियो और फ़ोटो मीडिया और सोशल मीडिया पर शेयर किए गए, लेकिन हममें से कितने लोगों ने उन्हें देखने की परवाह की, ईरान पर अमेरिका-इज़राइल की बमबारी में एक महीने से ज़्यादा समय से, ईरान के शहर मिनाब में 170 से ज़्यादा लड़कियों और टीचरों के अलावा, कई लोग मारे गए हैं। 24 मार्च को, दर्जनों औरतें रोम की सड़कों पर हाथ में हाथ डाले, नंगे पैर मार्च कर रही थीं। ये गाज़ा और इज़राइल की माँएँ थीं। उनके बच्चे या रिश्तेदार हमास की हिंसा और इज़राइल द्वारा लिए गए बदले के शिकार हुए थे। उनका मैसेज ज़ोरदार और साफ़ था-इज़राइल और गाज़ा दोनों के रहने वाले खुद को आदम और हव्वा की औलाद मानते हैं, और उन्हें बस शांति चाहिए। यह मार्च उन लोगों के लिए एक सबक था जो सोचते हैं कि हर इज़राइली गाज़ा को जला देना चाहता है। ये औरतें 25 मार्च को पोप लियो से मिलीं। पोप पहले ही शांति की अपील कर चुके थे। लेकिन क्या उन्होंने इन मांओं के कहने पर अमेरिका या यूरोप से बात की? तब से उनके रिएक्शन की कोई खबर नहीं है।

इस युद्ध मेंअमेरिकी सेना, उपकरण और मध्य देश में बेस भी में खो देता हैऔर फिर कहा कि मैं असलऔर ट्रम्प ने देश से कहा युद्ध मेंअमेरिकी जीत गया हैलेकिन वास्तव में, कोई नहीं जीता है,ईरान देश को अब शांति से आपसी तालमेल से इसे खत्म करना चाहिएक्योंकि अमेरिका का युद्ध का इतिहास दूसरे विश्व युद्ध में 1945में अंत में हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराने तक का है।द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में, 6 और 9 अगस्त 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर दो परमाणु बम गिराए। इन हवाई बमबारी में 150,000 से 246,000 लोग मारे गए, जिनमें से अधिकांश नागरिक थे। ये परमाणु हथियारों का सशस्त्र संघर्ष में पहला और एकमात्र प्रयोग था। हम बौनों के ज़माने में जी रहे हैं, लीडर्स के नहीं। वर्ल्ड वॉर द्वद्व से पहले और उसके ठीक बाद दुनिया ने महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला जैसे बड़े लोगों को देखा, जिनके कामों, अपीलों और दलीलों का बहुत वज़न था और दुनिया भर में उनकी गूंज सुनाई दी। उन्होंने अपनी जागृति से दुनिया को जगाए रखा और ज़िंदा रखा। उनसे प्रेरित होकर, आम लोगों ने अन्याय के खिलाफ़ मिलकर आवाज़ उठाई। 8 जून, 1972 की बात है। वियतनाम के ट्रांग बांग इलाके में बच्चे अमेरिका के सपोर्ट वाले हमलों से बचने के लिए अपनी सुरक्षा के लिए भाग रहे थे। नौ साल की किम फुक, वियतनाम में युद्ध से हुए भयानक हालात का उदाहरण बन गई, जब उसकी पीठ पर नेपाम के हमले में जलने के बाद, वह बिल्कुल नंगी दौड़ती हुई मारी गई। युद्ध का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है, जिसमें जान-माल की भारी हानि, आर्थिक मंदी, बुनियादी ढांचे का विनाश और गहरा मानवीय संकट शामिल है। यह न केवल देशों की सीमाओं को बदलता है और राजनीतिक स्थिरता को बाधित करता है, बल्कि पीढ़ियों तक मनोवैज्ञानिक आघात और सामाजिक उथल-पुथल भी छोड़ता है। युद्ध के प्रमुख परिणामों को इन बिंदुओं में समझा जा सकता है।

जन-धन की हानि हुई

युद्ध में सैनिकों और नागरिकों की भारी मृत्यु होती है, साथ ही संपत्ति, घरों और शहरों का विनाश होता है। आर्थिक मंदी और संकट- युद्धों के कारण व्यापार बाधित होता है, मुद्रास्फीति (महंगाई) बढ़ती है और देशों पर भारी कर्ज का बोझ पड़ता है। ऊर्जा और भोजन की आपूर्ति श्रृंखला टूट जाती है। राजनीतिक और भौगोलिक परिवर्तन- युद्ध के परिणामस्वरूप सरकारें गिर सकती हैं, नए राष्ट बन सकते हैं और अंतरराष्टीय संबंध बदल जाते हैं (जैसे, प्रथम विश्व युद्ध के बाद साम्राज्यों का अंत)। शरणार्थी और विस्थापन- युद्ध के कारण लाखों लोग बेघर हो जाते हैं और शरणार्थी बनकर दूसरे देशों में जाने को मजबूर होते हैं। दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक आघात- युद्ध न केवल शारीरिक घाव देता है, बल्कि सैनिकों और नागरिकों में पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं छोड़ जाता है। पर्यावरणीय क्षति- विस्फोटों और हथियारों के उपयोग से भूमि, जल और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है। भगवान राम और रावण के युद्ध में भगवान राम का संदेश धर्म, न्याय और करुणा की स्थापना करना था, न कि केवल विनाश। उन्होंने रावण को सुधारने का अंतिम अवसर (शांति प्रस्ताव) दिया, जो दर्शाता है कि युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए। उनका मुख्य संदेश अधर्म पर धर्म की विजय और युद्ध में भी मर्यादा व नीति का पालन करना था। युद्ध में भगवान राम के संदेश के मुख्य बिंदु- धर्म और न्याय की सर्वोच्चता- राम का युद्ध व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए था। शांति का प्रयास- उन्होंने अंगद को शांति प्रस्ताव के साथ भेजा, यह स्पष्ट करने के लिए कि युद्ध से पहले हर संभव समाधान तलाशा जाना चाहिए। मर्यादा और नैतिकता- युद्ध के दौरान भी, उन्होंने नियमों का पालन किया और पराजित या निहत्थे शत्रु पर प्रहार न करने जैसी मर्यादाओं का पालन किया। समावेशिता- उन्होंने वनवासियों, वानरों और सभी जातियों को साथ लेकर यह संदेश दिया कि न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एकता आवश्यक है। शत्रु के प्रति सम्मान- रावण के वध के बाद, राम ने विभीषण से कहा कि शत्रु के मरणोपरांत बैर समाप्त हो जाता है और रावण को सम्मानजनक अंतिम संस्कार दिलाया। अहंकार का नाश- राम ने रावण के माध्यम से यह संदेश दिया कि अत्यधिक शक्ति और अहंकार ही विनाश का कारण बनते हैं।

(यह लेखक के निजी विचार हैं) -साभार

शब्द पहेली - 8686

■	1		■	2	3		4	5
6		■	7			■	8	
9		10	■	11			■	
■	12		13	■		■	14	
15	■	16				17	■	
18		■		■	19		20	■
	■	21		22	■	23		24
25	26	■	27			■	28	
29			■		■	30		■

बाएँ से दाएँ

1. आस्तिक, अनुगामी, पूजक-2
2. रख-रखाव-2,3
6. देह, बदन-2
7. कारण-3
8. तपस्या-2
9. बंदूकधारी (अंग्रेजी-3)
11. पति की बहन-3
12. प्रतिज्ञा, वचन-3
14. पिता, डैडी-2
16. मन मोहने वाला-5
18. आनंदित-2
19. लवण, खार-3
21. बख्तरबंद, आवरण-3
23. पासों से भविष्य जानना-3
25. आमिर व काजोल की फिल्म-2
27. मुलायम, कोमल-3
28. उस समय-2
29. भ्रमण, घूमना-3,
30. कोलाहल-2

ऊपर से नीचे

1. खतरनाक-4
2. सनम, बालम-3
3. रहने का तरीका-3,3
4. चावल-2
5. बिजली का कौंधना-5
6. कौवा, काग-2
10. सांभर जैसा खाद्य पदार्थ-3
13. मन को भाने वाला-5
15. सहयात्री-5
17. कटि-3
20. निम्न, न्यूनतम-4
22. उत्कर्ष-3
24. अधर, होठ-2
26. संबोधन-2

शब्द पहेली - 8685 का हल

■	क	वि	ता	■	क	या	स	■
भ	ला	■	क	■	री	■	ही	न
र	■	म	त	ल	ब	■	■	ह
म	द	द	■	क्ष	■	फि	तू	र
■	■	भ	क्त	■	शी	त	■	■
से	हा	रा	■	यं	■	र	ज	त
ह	■	■	ज	हा	ल	त	■	मी
त	ल	■	मा	■	की	■	आ	ज
■	ब	हा	व	■	र	वा	ना	■

Jagrutidaur.com, Bangalore

दैनिक पंचांग

4 अप्रैल 2026 को सूर्योदय के समय की ग्रह स्थिति

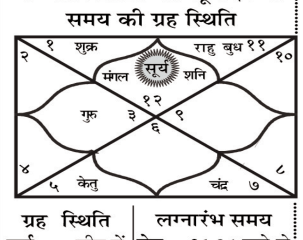

ग्रह	स्थिति
सूर्य	मीन में
चंद्र	तुला में
मंगल	मीन में
बुध	कुंभ में
गुरु	मिथुन में
शुक्र	मेष में
शनि	मीन में
राहु	कुंभ में
केतु	सिंह में

राहुकाल 9.00 से 10.30 बजे तक

लग्नारंभ समय	
मेष	06.24 बजे से
वृष	08.04 बजे से
मिथुन	10.02 बजे से
कर्क	12.16 बजे से
सिंह	14.32 बजे से
कन्या	16.44 बजे से
तुला	18.54 बजे से
वृश्चिक	21.09 ब.से
धनु	23.25 बजे से
मकर	01.30 बजे से
कुंभ	03.17 बजे से
मीन	04.50 बजे से

शनिवार 2026 वर्ष का 94 वा दिन
दिशाशूल पूर्व **ऋतु** बसंत।
विक्रम संवत् 2083
शक संवत् 1948
मास चैत्र **पक्ष** शुक्ल
तिथि द्वितीया 10.10 बजे को समाप्त।
नक्षत्र स्वाती 21.36 बजे को समाप्त।
योग हर्षण 14.17 बजे को समाप्त।
करण गर 10.10 बजे तदनन्तर वणिज 23.02 बजे को समाप्त।
चन्द्रायु 15.9 घण्टे
रवि क्रान्ति उत्तर 05° 37'
सूर्य उत्तरायन
कलि अहर्गण 1872669
जूलियन दिन 2461134.5
कलियुग संवत् 5128
कल्पारंभ संवत् 1972949128
सृष्टि ग्रहारंभ संवत् 1955885128
वीरनिर्वाण संवत् 2552
हिजरी सन् 1447
महीना सव्वाल
तारीख 15

दिन का चौघड़िया				रात का चौघड़िया			
काल	05.55 से	07.23 बजे तक		लाभ	05.37 से	07.10 बजे तक	
शुभ	07.23 से	08.51 बजे तक		उद्वेग	07.10 से	08.42 बजे तक	
रोग	08.51 से	10.19 बजे तक		शुभ	08.42 से	10.14 बजे तक	
उद्वेग	10.19 से	11.46 बजे तक		अमृत	10.14 से	11.47 बजे तक	
चर	11.46 से	01.14 बजे तक		चर	11.47 से	01.19 बजे तक	
लाभ	01.14 से	02.42 बजे तक		रोग	01.19 से	02.51 बजे तक	
अमृत	02.42 से	04.10 बजे तक		काल	02.51 से	04.23 बजे तक	
काल	04.10 से	05.37 बजे तक		लाभ	04.23 से	05.56 बजे तक	

चौघड़िया शुभाशुभ- शुभत्व श्रेष्ठ शुभ, अमृत व लाभ, **मध्यम** चर, **अशुभ** उद्वेग, रोग व काल। सभी समय भारतीय मानक समय की मध्य रेखा बिन्दु के आधार पर है अतः आप अपने स्थानीय समयानुसार ही देखें। Jagrutidaur.com, Bangalore

न्यूज इन शॉर्ट

जिले के प्रतिभावान खिलाड़ियों से वर्ष 2025 की राज्य स्तरीय खेलवृत्ति हेतु आवेदन आमंत्रित

उमरिया । संचालनालय खेल और युवा कल्याण, मध्यप्रदेश भोपाल 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के मध्य आयोजित अधिकृत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पदक विजेता उमरिया जिले के प्रतिभावान खिलाडियों से वर्ष 2025 की राज्य स्तरीय खेलवृत्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं। अधिकृत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को राशि रुपये 10000, रजत पदक विजेता खिलाड़ी को राशि रुपये 8000 एवं कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी को राशि रूपये 6000 खेलवृति राशि प्रदान करने का प्रावधान है।अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं जिला एवं युवा कल्याण अधिकारी सीताराम सत्या ने बताया कि वर्ष 2025 के खेलवृत्ति हेतु आवेदन 31 मई 2026 तक कार्यालय जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी गांधी चौक काली मंदिर के पास उमरिया में स्वीकार किए जा सकेंगे। खेलवृत्ति हेतु आवेदन कार्यालय जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी जिला उमरिया से प्राप्त कर सकते हैं। दिनांक 31 मई 2026 के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

उर्वरक विक्रेता ई-विकास पोर्टल के माध्यम से ही करेंगे खाद का वितरण

उमरिया` कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला उमरिया के निर्देशानुसार, जिले में उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने और वितरण प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से सभी निजी एवं शासकीय उर्वरक विक्रेताओं के लिए कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। उप संचालक कृषि संग्राम सिंह ने जिले के सभी खाद विक्रेताओं (निजी एवं सहकारी समितियाँ) से कहा है कि ई विकास पोर्टल से जारी ई टोकन के माध्यम से उर्वरक का वितरण सुनिश्चित करेंगे। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही खाद का विक्रय करें। दुकान पर उर्वरक की स्टॉक स्थिति और मूल्य सूची (रेट बोर्ड) प्रदर्शित करना अनिवार्य है। भौतिक स्टॉक और ई विकास पोर्टल में स्टॉक का मिलान होना आवश्यक है। इसमें किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर संबंधित विक्रेता के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 के तहत सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उप संचालक कृषि ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी आवश्यकतानुसार ही उर्वरक का क्रय ई टोकन के माध्यम से करें।

शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने वाला आरोपी गिरफ्तार

गोहपारू पुलिस ने शादी का झूठा वादा कर वर्षों तक शारीरिक शोषण करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। फरियादिया द्वारा थाना में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी रज्जन बैगा पिता सौखी लाल बैगा ने वर्ष 2016 में उसे शादी का प्रलोभन देकर पहली बार दुष्कर्म किया था। इसके पश्चात आरोपी उसे अपने साथ सूरत (गुजरात) ले गया, जहाँ लगभग 7-8 वर्षों तक पति-पत्नी की तरह साथ रखकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा। एक वर्ष पूर्व आरोपी फरियादिया को सूरत में छोड़कर वापस अपने गांव भाग आया। जब फरियादिया ने गांव लौटकर शादी का दबाव बनाया, तो आरोपी टाल-मटोल करने लगा और 24 फरवरी 2026 को उसने किसी अन्य महिला से शादी कर ली। फरियादिया की शिकायत पर थाना गोहपारू में आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।उक्त कार्यवाही विवेचना के दौरान आरोपी रज्जन बैगा की पता तलाश की गई। आरोपी रज्जन बैगा पिता सौखी लाल बैगा उम्र 30 साल निवासी ग्राम गुढ़ा थाना गोहपारू का अपने ग्राम गुढ़ा घर पर दस्तयाब हुआ जिसें 03.04.2026 को गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

साधना सप्ताह के सफल आयोजन हेतु सी ई ओ जिला पंचायत नोडल अधिकारी नियुक्त

उमरिया। आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय भोपाल के अनुसार साधना सप्ताह का 8 अप्रैल 2026 तक आयोजन किया जाना है। साधना सप्ताह के दौरान मिशन कर्मयोगी अंतर्गत आई गॉट पोर्टल पर उपलब्ध अधिक से अधिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की पूर्णता जिले के समस्त शासकीय सेवकों ,संविदा कर्मियों के द्वारा किया जाना है।

8 करोड़ की मॉडल रोड पर अव्यवस्था का कब्जा

यातायात सुधार की मंशा पर सवाल, बुढ़ार रोड की आधुनिक सड़क बनी पार्किंग जोन, आधा हिस्सा धूल में दबा; उपयोग और निगरानी पर उठे गंभीर प्रश्न

विजय मत, शहडोल

शहडोल शहर में आधुनिक और सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से बुढ़ार रोड पर करीब 8 करोड़ रुपये की लागत से तैयार की गई मॉडल रोड अब अपनी बदहाल स्थिति के कारण चर्चा का विषय बन गई है। जिस सड़क को शहर के विकास और सुगम आवागमन का प्रतीक माना जा रहा था, वही अब अव्यवस्था, अनियोजित उपयोग और लापरवाही का उदाहरण बनती जा रही है। सड़क पर एक ओर जहां वाहनों का दबाव सही ढंग से संचालित नहीं हो पा रहा है, वहीं दूसरी ओर इसका बड़ा हिस्सा ऐसे उपयोग में जा रहा है, जो इसके मूल उद्देश्य से पूरी तरह अलग है।

सड़क पर अवैध पार्किंग का बढ़ता दबाव

मॉडल रोड के एक बड़े हिस्से पर इन दिनों चार पहिया वाहनों की अवैध पार्किंग का कब्जा दिखाई दे रहा है। सड़क किनारे ही नहीं, बल्कि कई स्थानों पर बीच तक वाहन खड़े कर दिए जाते हैं, जिससे यातायात का दायरा सीमित हो जाता है और वाहन चालकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। स्थिति यह है कि कई बार दोपहिया और चार पहिया वाहनों को निकलने के लिए जगह तक नहीं मिलती, जिससे जाम जैसी परिस्थितियां बन जाती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि इस पर समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया, तो यह समस्या और विकराल रूप ले सकती है।

धूल-रेत से ढका अनुपयोगी हिस्सा

सड़क का दूसरा हिस्सा, जहां वाहनों की आवाजाही लगभग नहीं के बराबर है, वहां धूल और रेत की मोटी परत जमी हुई साफ देखी जा सकती है। यह न केवल सड़क के कम उपयोग को दर्शाता है, बल्कि रखरखाव में कमी को भी उजागर करता है। आधुनिक डिजाइन और निर्माण के बावजूद यदि सड़क का एक बड़ा हिस्सा उपयोग में ही नहीं आ रहा, तो यह योजना और क्रियान्वयन दोनों पर सवाल खड़े करता है।

यातायात सुधार की मंशा पर असर

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस मॉडल रोड से उन्हें बेहतर यातायात सुविधा की उम्मीद थी, लेकिन मौजूदा हालात में यह उद्देश्य अधूरा नजर आ रहा है। अनियंत्रित पार्किंग और अव्यवस्थित संचालन के कारण न तो यातायात सुगम हो पा रहा है और न ही सड़क का प्रभावी उपयोग हो रहा है। कई लोगों का मानना है कि सड़क बनने के बाद भी शहर के इस हिस्से में यातायात की स्थिति में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला है।

तकनीकी दृष्टिकोण से बढ़ती चिंता

इंजीनियरों का कहना है कि किसी भी डामर सड़क की मजबूती उसके नियमित उपयोग पर निर्भर करती है। जिस हिस्से पर वाहन नहीं चलते, वह धीरे-धीरे कमजोर होने लगता है और जल्दी खराब होने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में यदि सड़क का एक बड़ा भाग अनुपयोगी बना रहता है, तो यह भविष्य में अतिरिक्त मरम्मत और खर्च का कारण बन सकता है।

उद्देश्य से भटकती परियोजना की तस्वीर

स्थानीय लोगों के अनुसार, करोड़ों रुपये खर्च कर बनाई गई इस मॉडल रोड का उद्देश्य शहर में बेहतर यातायात व्यवस्था स्थापित करना और सौंदर्य बढ़ाना था, लेकिन वर्तमान स्थिति में यह सड़क धीरे-धीरे पार्किंग स्थल में तब्दील होती जा रही है। नागरिकों का कहना है कि यदि अवैध पार्किंग पर सख्ती नहीं की गई और नियमित सफाई व निगरानी की व्यवस्था नहीं बनाई गई, तो यह महत्वपूर्ण विकास कार्य अपनी उपयोगिता खो सकता है।

जवाबदेही और निगरानी पर सवाल

इस पूरी स्थिति के बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इस मॉडल रोड की निगरानी और संचालन की जिम्मेदारी किसके पास है। अवैध पार्किंग को रोकने, सड़क को साफ-सुथरा रखने और यातायात को व्यवस्थित करने के लिए किस विभाग को जिम्मेदार ठहराया जाए, इस पर स्पष्टता का अभाव नजर आ रहा है।

दिनदहाड़े ज्वेलर्स शॉप में स्मार्ट चोरी , ग्राहक बनकर आईं महिलाएं 3.5 लाख का सोना ले उड़ीं

विजय मत, उमरिया

जिले के पाली कस्बे में गुरुवार दोपहर एक ज्वेलरी दुकान पर हुई शातिराना चोरी ने व्यापारियों को चौंका दिया। मेन रोड स्थित प्रकाश चौक के पास संचालित श्रृंगार ज्वेलर्स में दो अज्ञात महिलाएं ग्राहक बनकर पहुंचीं और कुछ ही मिनटों में करीब 3 लाख 50 हजार रुपये कीमत के सोने के जेवर लेकर रफूचक्कर हो गई। दुकान संचालक 65 वर्षीय पुरुषोत्तम लाल सोनी ने अपने पुत्र विकास कुमार सोनी के साथ थाना पाली पहुंचकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि दोपहर करीब 12.15 से 1 बजे के बीच दो महिलाएं दुकान में आई। एक महिला गहरे हरे रंग की साड़ी पहने हुई थी, जबकि दूसरी हल्के गुलाबी रंग के सलवार सूट में थी। दोनों ने सामान्य ग्राहक की तरह व्यवहार करते हुए पहले सोने के लॉकेट दिखाने को कहा। दुकानदार जब उन्हें आभूषण दिखाने में व्यस्त हो गया, तभी महिलाओं ने बड़ी

चालाकी से दुकान के दराज में रखे पुराने सोने के जेवरों पर हाथ साफ कर दिया। चोरी किए गए जेवरों में लगभग 36 ग्राम सोना शामिल है, जिसमें दो हार, एक मुंगावली अंगूठी और एक सोने की अढ़ी शामिल बताई गई है। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि दोनों महिलाएं जाते समय अपना नाम शिवांगी कुशवाहा बताकर गई और यह कहकर निकलीं कि वे अगले दिन आकर सामान लेंगी। इस बहाने उन्होंने दुकानदार को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया और बिना किसी शक के आराम से दुकान से निकल गईं। कुछ देर बाद जब पुरुषोत्तम सोनी ने अपनी दराज चेक की, तो जेवर गायब देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत थाना पाली पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात महिलाओं के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 305 (ए) के तहत मामला कायम कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी विजय सेन ने बताया कि यह चोरी की घटना है, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।

आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि संदिग्ध महिलाओं की पहचान की जा सके। उन्होंने कहा कि आरोपियों को जल्द पकड़ने के प्रयास लगातार जारी हैं। इस घटना के बाद स्थानीय बाजार के व्यापारियों में दहशत का माहौल है। दिनदहाड़े इस तरह की वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। व्यापारी अब अपनी दुकानों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने की बात कह रहे हैं, वहीं पुलिस भी जल्द मामले का खुलासा करने का दावा कर रही है।

एनएसयूआई प्रतिनिधि मंडल ने सौंपा ज्ञापन अतिशीघ्र पट्टा वितरण की उठाई मांग

विजय मत, उमरिया

भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रतिनिधि मंडल द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत झुग्गी-झोपड़ी निवासियों एवं भूमिहीन हितग्राहियों को धारणाधिकार (पट्टा) प्रदान कर शीघ्र पट्टा वितरण किए जाने की मांग को लेकर माननीय मुख्यमंत्री एवं कलेक्टर जिला उमरिया के नाम से ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत पात्र हितग्राहियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जानी है, लेकिन जिला उमरिया के कई पात्र परिवार भूमि संबंधी दस्तावेजों के अभाव में योजना से वंचित हैं। ऐसे में शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार नगरीय क्षेत्रों में निवासरत झुग्गी-झोपड़ी एवं भूमिहीन परिवारों को धारणाधिकार (पट्टा) प्रदान करना आवश्यक है, ताकि वे योजना का लाभ प्राप्त कर सकें। इस अवसर पर मो. असलम शेर ने कहा कि सर्वे हो जाने के बावजूद आज दिनांक तक हितग्राहियों को पट्टा वितरित नहीं किया गया है। आगे उन्होंने कहा कि जिले के पात्र हितग्राहियों को अतिशीघ्र पट्टा वितरण किया जाए, जिससे वे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेकर अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकें। ज्ञापन सौंपते समय कृष्ण कांत तिवारी (जिला उपाध्यक्ष), पल्लवी असाटी (जिला सचिव), रोशनी श्याम (जिला सचिव), खुशी मोगरे (कॉलेज अध्यक्ष), प्रतिमा रैदास नावेद अंसारी,सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

चौकी केशवाही पुलिस द्वारा, फरार दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार

विजय मत, शहडोल

चौकी केशवाही में गुम इंसान दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए लगातार तलाश की जा रही थी। 25 मार्च को गुमशुदा युवती को पुलिस द्वारा दस्तयाब किया गया। पीड़िता के कथन लेखबद्ध किए गए तथा संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई।

पीड़िता के बयानों एवं साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सचिन सिंह कंवर (पिता उदयभान सिंह कंवर), निवासी ग्राम केशवाही के विरुद्ध अपराध धारा एवं बीएनएस के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना के बाद से ही आरोपी सचिन सिंह कंवर अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गया था तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपी को 3 अप्रैल को गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। उक्त कार्यवाही थाना प्रभारी बुढार के नेतृत्व में, उपनिरीक्षक गंगा सिंह मार्को, राजभान सिंह, आरक्षक उमेश राठौर एवं आरक्षक जितेंद्र राठौर की सराहनीय भूमिका रही।

दिवंगत साहित्यकारों को प्रलेस की शोक संवेदना

शहडोल। म.प्र. प्रगतिशील लेखक संघ शाखा शहडोल के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने देश के दिवंगत साहित्यकारों के प्रति गहरा दुःख व्यस्त किया है। एक शोक संवेदना संदेश में कहा है कि हिन्दी साहित्य के शीर्ष लेखक, वरिष्ठ कवि और समर्थ कथाकार विनोद कुमार शुक्ल (88 वर्ष) का विगत दिवस 22 दिसम्बर 2025 को लम्बी बीमारी के बाद एम्स रायपुर में निधन हो गया। उन्हें साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार 21 नवंबर 2025 को ही मिला था। उनकी कविताओं और उपन्यासों की अनेक किताबें पाठकों की चेतना को नया आयाम देने में कामयाब रहीं। एक उपन्यास पर फिल्म भी बनाई गई है। उनकी रचनाओं का कई भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। श्री शुक्ल के निधन पर प्रधानमंत्री का भी शोक संदेश आया है। दुःख की घड़ी यह भी आई जब 29 दिसम्बर 2025 को भिलाई स्टील प्लान्ट से सेवानिवृत वरिष्ठ कवि, आलोचक नासिर अहमद सिकंदर (64 वर्ष) का आकस्मिक निधन हो गया। वे प्रगतिशील मूल्यों के शसक्त सिपाही थे।इसी प्रकार हिंदी साहित्य के प्रख्यात कहानीकार ज्ञानरंजन (90 वर्ष) ने 07 जनवरी 2026 बुधवार को जबलपुर में अपने जीवन की अन्तिम सांसे ली। उनकी कहानियां हिन्दी जगत की यात्रा के लिए मील का पत्थर साबित हुई। प्रगतिशील लेखक संघ शहडोल उक्त तीनों दिवंगत जनों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है और शोकाकुल परिजनों के दुःख में अपनी सहभागिता व्यक्त करता है। शोक सभा में शैलेन्द्र जार्ज अध्यक्ष एवं विजय उपाध्याय महासचिव प्रलेस इकाई शहडोल शामिल थे।

रीवा महाराजा एवं पूर्व मंत्री ने उमरिया को उड़ान योजना में शामिल करने कि उठाई मांग

उमरिया। रीवा महाराज एवं पूर्व मंत्री पुष्पराज सिह ने जिला मुख्यालय उमरिया के सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू चर्चा करते हुए कहा कि उमरिया जिले को केंद्र सरकार कि उडान योजना में शामिल किए जाने की मांग उठाई है। उन्होने बताया कि नागर विमानन मंत्री किंजारापु राममोहन नायडू को एक औपचारिक पत्रकर मांग उन तक पहुचाई गई है। इस दौरान उन्होने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के विमानन क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है और उड़ान योजना के माध्यम से कई छोटे शहरों को हवाई सेवाओं से जोड़ा गया है। ऐसे में उमरिया जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र को इससे जोड़ना बेहद आवश्यक है। उन्होंने बताया कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान देश के मध्य भाग में स्थित एक प्रमुख पर्यटन केंद्र है जो कर्क रेखा के आसपास आता है। इसकी खासियत यह है कि यह कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना टाइगर रिजर्व और संजय दुबरी राष्ट्रीय उद्यान जैसे प्रमुख वन क्षेत्रों के लगभग समान दूरी पर स्थित है। इसके अलावा वाराणसी, बिलासपुर और झांसी जैसे बड़े शहरों से इसकी दूरी 200 से 350 किलोमीटर के बीच है जबकि जबलपुर, ग्वालियर, शहडोल और रीवा जैसे शहर और भी नजदीक हैं।

रीवा महाराजा पुष्पराज सिंह ने कहा कि वाराणसी और जबलपुर पहले से ही हवाई सेवाओं से जुड़े हुए हैं और हाल ही में रीवा को भी हवाई सुविधा मिलने से इस क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाएं और बढ़ गई हैं। यदि उमरिया को भी उड़ान योजना में शामिल कर लिया जाता है तो यह पूरे विंध्य और महाकौशल क्षेत्र के लिए एक बड़ा बदलाव साबित होगा। उन्होंने अपने पत्र में तीन प्रमुख बिंदुओं को विशेष रूप से रखा है। पहला, उमरिया में हवाई सेवा शुरू होने से देश के विभिन्न शहरों से आने वाले पर्यटकों के लिए बांधवगढ़ और आसपास के राष्ट्रीय उद्यानों तक पहुंचना आसान और तेज हो जाएगा। दूसरा, उमरिया एक आदिवासी बहुल जिला है जहां हवाई संपर्क स्थापित होने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। तीसरा, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बांधवगढ़ को बौद्ध धर्म के प्राचीनतम साक्ष्यों में शामिल किए जाने से धार्मिक पर्यटन की संभावनाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा भी इस क्षेत्र की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता का उल्लेख किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि आने वाले समय में यहां पर्यटकों की संख्या में बड़ा इजाफा हो सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में पुष्पराज सिंह ने कहा कि बांधवगढ़ के होटल व्यवसायी, गाइड, जीप मालिक संघ और स्थानीय जनप्रतिनिधि इस मांग का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि उमरिया को उड़ान योजना में शामिल कर क्षेत्र के विकास को नई दिशा दी जाए ताकि यहां के आदिवासी समुदाय को रोजगार और आत्मनिर्भरता के बेहतर अवसर मिल सकें।

अनदेखी

बड़े वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही और ठेलों की मनमानी से बिगड़ी स्थिति

सब्जी मंडी में अव्यवस्था का अंबार, जाम और विवाद से परेशान व्यापारी

विजय मत, शहडोल

शहडोल की प्रमुख सब्जी मंडी, जो कभी शहर की रोजमर्रा की जरूरतों का सुव्यवस्थित केंद्र मानी जाती थी, अब अव्यवस्था, जाम और अतिक्रमण की समस्याओं का अड्डा बनती जा रही है। यहां हर दिन लगने वाली भीड़ के बीच बड़े वाहनों की बेलगाम एंट्री और ठेला संचालकों की मनमानी ने हालात इतने बिगाड़ दिए हैं कि ग्राहकों का निकलना तक मुश्किल हो गया है। स्थिति यह है कि मंडी अब सुविधा से ज्यादा परेशानी का कारण बनती जा रही है, जबकि जिम्मेदार नगर पालिका का अभियान कागजों तक सिमट कर रह गया है।

दिनभर जाम से जूझते ग्राहक और व्यापारी

शहडोल शहर की प्रमुख सब्जी मंडी इन दिनों अव्यवस्था और जाम की गंभीर समस्या से जूझ रही है। मंडी क्षेत्र में लगातार बढ़ती भीड़, बड़े वाहनों का बेतरतीब प्रवेश और ठेला संचालकों की मनमानी के चलते हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इससे व्यापारियों के साथ-साथ आम लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

ठेला संचालकों की मनमानी से बढ़ी अव्यवस्था

व्यापारियों का कहना है कि मंडी में बड़े मालवाहक वाहन बिना किसी निर्धारित समय के प्रवेश कर रहे हैं, जिससे दिन के व्यस्त समय में जाम की स्थिति बन जाती है। संकरी सड़कों पर जब भारी वाहन खड़े हो जाते हैं तो ग्राहकों के लिए निकलना मुश्किल हो जाता है। कई बार छोटे-छोटे विवाद भी सामने आते हैं, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो जाता है।

व्यापारियों ने रखीं ठोस मांगें

मंडी परिसर में ठेला संचालकों द्वारा मनमाने ढंग से ठेले खड़े किए जा रहे हैं। दुकानों के सामने ही ठेले लगा दिए जाने से ग्राहकों के लिए रास्ता तक नहीं बचता। स्थायी दुकानदारों का कहना है कि इस वजह से उनका व्यापार प्रभावित हो रहा है और ग्राहक असुविधा के चलते मंडी आने से कतराने लगे हैं।

नपा का अभियान ठंडे बस्ते में

व्यापारियों ने नगर पालिका से मांग की है कि मंडी क्षेत्र में बड़े वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए और केवल निर्धारित समय में ही माल की ढुलाई की अनुमति दी जाए। इसके अलावा ठेला संचालकों के लिए अलग स्थान चिन्हित कर उन्हें वहीं तक सीमित किया जाए, ताकि मुख्य मार्ग और दुकानों के सामने भीड़भाड़ की स्थिति समाप्त हो सके।

फिर लौटे पुराने हालात, बढ़ा आक्रोश

नगर पालिका द्वारा कुछ समय पहले मंडी की व्यवस्था सुधारने के लिए अभियान चलाने की बात कही गई थी। बेतरतीब ठेलों और सड़क तक बढ़ी दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की योजना बनाई गई थी, लेकिन यह अभियान कुछ दिनों तक ही सीमित रहा और फिर पूरी तरह ठंडे बस्ते में चला गया।

न्यूज इन शॉर्ट

जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जिले में जल मंदिरो का किया गया शुभारंभ

शहडोल। 'जल गंगा संवर्धन अभियान' के अंतर्गत शहडोल जिले के समस्त जनपद पंचायतों में जल संरक्षण व संचयन के कार्य किए जा रहे है। जन अभियान परिषद् के सदस्यों में द्वारा जयसिंहनगर के बसोंहरा और भटीगवांखुर्द में नवांकुर संस्था एवं प्रस्फुटन समितियों के सहयोग से ग्रीष्म ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जल मंदिर(प्याऊ)का शुभारंभ किया गया। जल मंदिर के शुभारंभ से मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों को शीतल पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित होगी। साथ ही उपस्थित जनों को जल के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए शपथ भी दिलाई गई।

विद्युत समाधान योजना की अवधि 15 मई तक बढ़ाई गई

शहडोल। राज्य सरकार की समाधान योजना 2025-26 के द्वितीय व अंतिम चरण को 15 मई तक बढ़ा दिया गया है। बिजली उपभोक्ताओं से आग्रह किया गया है कि यह सरचार्ज में छूट का अंतिम अवसर है, इसका लाभ जरूर लें।बकायादार उपभोक्ताओं के लिए योजना बनी वरदान यह योजना उन बकायादार उपभोक्ताओं के लिए वरदान बनी है जो सरचार्ज के कारण मूलधन राशि जमा नहीं कर पा रहे थे। अब उन्हें समाधान योजना में सरचार्ज में 50 से लेकर 90 प्रतिशत तक छूट के साथ एकमुश्त अथवा किस्तों में भुगतान करने का विकल्प मिल रहा है। समाधान योजना में तीन माह से अधिक के बकायादार उपभोक्ताओं को एकमुश्त राशि जमा करने पर 90 प्रतिशत तक सरचार्ज में छूट का लाभ दिया जा रहा है। ऐसे उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि यदि वे तीन माह से अधिक के बकाएदार हैं और योजना में अभी तक शामिल नहीं हो पाए वे अब 15 मई तक योजना में शामिल होकर अपना बकाया बिल एकमुश्त जमा करके 90 फीसदी तक सरचार्ज माफी का लाभ उठा सकते हैं।

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से मिलेगी मुफ्त बिजली और होगा पर्यावरण संरक्षण

शहडोल। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लागू की गई है। इस योजना के माध्यम से उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली मिलने के साथ पर्यावरण संरक्षण भी होगा। ताप विद्युत केन्द्रों से बिजली उत्पादन के लिए भारी मात्रा में कोयले का दहन किया जाता है जो पर्यावरण के प्रतिकूल है। सोलर पैनल पूरी तरह से निःशुल्क तथा पर्यावरण के अनुकूल है। बिजली का उपयोग करने वाले आवासीय घरों में सोलर पैनल लगवाकर बिजली के बिल में 30 से 70 प्रतिशत तक की कमी ला सकते हैं। कार्यपालन अभियंता विद्युत विभाग जितेंद्र गुप्ता ने बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत दो किलोवाट तक की क्षमता वाले छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए 30 हजार प्रति किलोवाट वित्तीय सहायता दी जाती है। इसी तरह तीन किलोवाट अथवा उससे अधिक क्षमता के सोलर पैनल लगवाने पर 78 हजार का अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि छत पर सोलर पैनल लगाने से प्रति किलोवाट 1300 यूनिट बिजली का साल भर में उत्पादन होता है। इस बिजली को नेट मीटरिंग वाली बिजली यानी ग्रिड से जोड़ने पर मासिक बिजली बिल में काफी कमी आती है। नेट मीटरिंग प्रक्रिया के द्वारा लगाया गया मीटर सोलर पैनल से प्राप्त बिजली तथा ग्रिड से ली गई बिजली का आकलन करता है। सोलर पैनल से उत्पादित बिजली यदि घरेलू उपकरणों में उपयोग से अधिक है तो उसे ग्रिड में भेज देता है। जब सोलर पैनल से बिजली का उत्पादन नहीं होता।

स्कूली वाहनों की सुरक्षा पर लापरवाही, 8 माह से जांच ठप

एलपीजी से चलने वाले वाहनों में हादसे का खतरा, विभागों के टकराव में अटकी कार्रवाई

विजय मत, शहडोल

शहडोल संभाग मुख्यालय शहडोल में स्कूली वाहनों की सुरक्षा को लेकर गंभीर अनदेखी सामने आई है। एलपीजी (लिक्विड पेट्रोलियम गैस) से संचालित वाहनों में संभावित हादसों की आशंका के बावजूद बीते 8 महीनों से इनकी कोई नियमित जांच नहीं की गई है। अप्रैल से स्कूल खुलने के बाद भी जिम्मेदार विभाग सक्रिय नहीं दिख रहे हैं, जिससे बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

जांच के बाद भी नहीं हुई दोबारा कार्रवाई

शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में डॉ. केदार सिंह ने स्कूली वाहनों की जांच के निर्देश दिए थे। इसके बाद अनपा खान द्वारा 29 जुलाई 2025 को जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान 18 वाहन सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करते हुए सड़कों पर चलते पाए गए। खास बात यह रही कि इनमें अधिकतर वाहन निजी और कान्वेंट स्कूलों से जुड़े थे। कार्रवाई के दौरान स्कूल प्रबंधन को 15 अगस्त से पहले व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बाद न तो पुनः जांच हुई और न ही सुधारों की कोई समीक्षा सामने आई।

अभिभावकों में बढ़ी चिंता

लगातार निगरानी के अभाव में अभिभावकों के बीच चिंता का माहौल है। उनका कहना है कि जिन वाहनों में उनके बच्चे रोजाना सफर कर रहे हैं, उनकी स्थिति और सुरक्षा मानकों की कोई जांच नहीं हो रही है। ऐसे में कभी भी गंभीर हादसा होने की आशंका बनी हुई है।

जुगाड़ से जिम्मेदारी से बच रहे स्कूल संचालक

निजी स्कूल संचालक जवाबदेही से बचने के लिए नए तरीके अपना रहे हैं। कई स्कूल अब अपनी बसें संचालित नहीं कर रहे, बल्कि बच्चों को मोहल्लों से गुजरने वाले निजी वाहनों से आने-जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इन वाहनों पर स्कूल का सीधा नियंत्रण नहीं होता, जिससे दुर्घटना की स्थिति में जिम्मेदारी तय करना मुश्किल हो जाता है। इन वाहनों में सुरक्षा मानकों का पालन भी संदिग्ध रहता है, जिससे बच्चों का सफर और अधिक जोखिम भरा हो गया है।

विभागों में तालमेल की कमी

स्कूली वाहनों की जांच को लेकर आरटीओ और यातायात विभाग के बीच तालमेल का अभाव भी उजागर हुआ है। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जांच का दायित्व यातायात विभाग का है। वहीं यातायात विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वाहनों के पंजीकरण और संचालन की जानकारी आरटीओ के पास होती है, इसलिए कार्रवाई भी उन्हें ही करनी चाहिए।

जांच अभियान पर अनिश्चितता बरकरार

दोनों विभागों के बीच जिम्मेदारी को लेकर जारी खींचतान के चलते जांच अभियान ठप पड़ा हुआ है। हालांकि यातायात विभाग की ओर से जल्द जांच शुरू करने की बात कही गई है, लेकिन अब तक इसका कोई स्पष्ट असर देखने को नहीं मिला है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच स्कूली बच्चों की सुरक्षा एक बार फिर सवालों के घेरे में है।

विकास कार्यों की धीमी चाल

विजय मत, शहडोल

संभागीय मुख्यालय में सीवर लाइन का कार्य हो या सड़कों के निर्माण का कार्य सब कुछ इतनी धीमी गति से चल रहा है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इन कार्यों को पूरा होने में सालों बीत जाएंगे। सीवर लाइन की डेडलाइन तो खत्म ही हो चुकी है मार्च में यह कार्य पूरा हो जाने की बात कही गई थी परंतु शहर के अंदर बड़े-बड़े खाई नुमा गड्ढे देखकर तो यही प्रतीत होता है 4 महीने और बीत जाएंगे बरसात आ जाएगी फिर भी यह कार्य पूरा हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। झूला पुल सीसी रोड का निर्माण पुलिस लाइन में अटक गया है । मत्स्य विभाग के सामने से शुरू हुआ यह कार्य क्यों रुक गया इसे देखने वाला कोई नहीं है इसी तरह इंदिरा चौक से बस स्टैंड के बीच बनने वाली 6 करोड रुपए की मॉडल रोड का निर्माण शुरू ही नहीं हुआ है। यह विकास कार्य नागरिकों व्यापारियों और नगर पालिका के बीच आपसी तालमेल न होने की वजह से अटका हुआ है । नगर पालिका द्वारा इस रोड के चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण हटाया जाना है । नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने हेतु नोटिस लोगों को दी गई है परंतु कुछ लोग हाई कोर्ट से स्थगन ले आए हैं । जो लोग हाईकोर्ट गए हैं उनका कहना है कि नगर पालिका के पास रोड का कोई नक्शा ही नहीं है और जिन नागरिकों का पट्टा है उन्हें नोटिस दी गई है यदि नगर पालिका को सड़क चौड़ी करना है तो पहले मुआवजा की कार्रवाई पूरी करनी होगी परंतु अभी तक नगर पालिका द्वारा मुआवजा की कोई कार्यवाही नहीं की गई है ऐसी स्थिति में एक नगर पालिका अधिकारी का स्थानांतरण हो गया है और दूसरी मुख्य नगर अधिकारी ने अपना कार्य भार ग्रहण करने के बाद काम शुरू कर दिया है परंतु जिस तरह से हाई कोर्ट स्टेडियम के मामले में जिला प्रशासन और नगर पालिका के अधिकारियों की खिंचाई कर रहा है उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि इंदिरा चौक से बस स्टैंड वाली मॉडल रोड का निर्माण कार्य शुरू होने में अभी काफी वक्त लगेगा।

झूला पुल वाली सड़क हो या बस स्टैंड वाली सड़क हजारों गड्ढों से लबालव इन सड़कों में आवागमन करने वाले नागरिकों को कितनी परेशानी होती है यह तो नागरिक ही बता सकते हैं। यदि हम बात करें राजेंद्र टॉकीज से पांडव नगर की तरफ जाने वाली सड़क का तो आप जान लीजिए कि यह एक मॉडल रोड है परंतु इन इन दिनों सीवर लाइन के विशाल गड्ढों के कारण स्कूलों और कॉलेज के बच्चों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस मार्ग पर कान्वेंट स्कूल, पॉलिटेक्निक कॉलेज, कन्या महाविद्यालय, भारत माता स्कूल, सरस्वती स्कूल एवं तमाम अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के बंगले बने हुए हैं । जयसिंहनगर क्षेत्र की विधायक श्रीमती मनीषा सिंह का कार्यालय एवं निवास दोनों ही पांडव नगर में है परंतु विकास कार्य की धीमी गति यह बता रही है कि इस गति को तेज करने में किसी का बस नहीं चल रहा है । ना तो प्रशासनिक अधिकारियों का और ना ही जन प्रतिनिधियों का। ऐसी स्थिति में बेचारा नागरिक करें तो कर क्या करे, कहां जाए, वह किसके पास जाकर अपनी परेशानी बताएं यह समझ में नहीं आता।

विजयमत विशेष
जन सरोकार
अजय जायसवाल

भविष्य से भेंट' कार्यक्रम के तहत अधिकारियों का विद्यालयों में संवाद आज

कलेक्टर ने अधिकारियों को विभिन्न विद्यालयों में आवंटित किया

विजय मत, शहडोल

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार शहडोल जिले में 1 अप्रैल से 4 अप्रैल 2026 तक ÷स्कूल चलें हम÷ अभियान के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 4 अप्रैल 2026 को ÷भविष्य से भेंट÷ कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रेरित करना और उनके उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में मार्गदर्शन प्रदान करना है। कार्यक्रम के तहत विभिन्न विभागों के अधिकारी, समाज के प्रतिष्ठित एवं अनुभवी व्यक्तित्व के रूप में विद्यालयों में पहुंचकर विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। वे अपने अनुभव साझा करते हुए बच्चों को शिक्षा के महत्व, करियर निर्माण एवं जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे।कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने अधिकारियों को विभिन्न विद्यालयों में आवंटित किया है, जहां वे निर्धारित समय पर उपस्थित होकर बच्चों के स्तर के अनुरूप एक कक्षाखंड में अध्यापन कार्य भी करेंगे तथा प्रेरक संवाद स्थापित करेंगे।कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे 4 अप्रैल को अनिवार्य रूप से अपने आवंटित विद्यालय में उपस्थित रहकर कार्यक्रम को सफल बनाएं तथा विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने में सक्रिय भूमिका निभाएं। जिला शिक्षा केंद्र शहडोल द्वारा कार्यक्रम की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और सभी विद्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

गंजरा नाला में महिला का मिला शव

उमरिया। जिले के बिरसिंहपुर पाली थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई, जब गंजरा नाला में एक महिला का शव तैरता हुआ मिला। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई और पुलिस को सूचना दी गई। मृतका की पहचान देवरति बसोर उम्र 40 वर्ष पति रामचरण बसोर, निवासी झिरिया मोहल्ला बिरसिंहपुर पाली के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि महिला बीते दिन से घर से बाहर थी और परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। इसी दौरान आज सुबह गंजारा नाला में शव मिलने की खबर सामने आई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही बिरसिंहपुर पाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पानी से बाहर निकलवाकर पंचनामा कार्रवाई शुरू की। प्रारंभिक जांच में किसी तरह के बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं, जिससे मामला संदिग्ध जरूर है लेकिन स्पष्ट नहीं हो सका है। प्रभारी थाना प्रभारी विजय सेन ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतका को एपिलेप्सी की बीमारी थी। घटना स्थल के पास एक मंदिर भी स्थित है, जहां बीते दिन भंडारे का आयोजन चल रहा था। आशंका जताई जा रही है कि महिला वहां गई होगी और किसी समय नाले के पास पहुंच गई होगी।

आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना से डेयरी व्यवसाय का सुनहरा अवसर

शहडोल। पशुपालन विभाग द्वारा दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना लागू की गई है। इस योजना में 75 प्रतिशत राशि बैंक ऋण के माध्यम से दी जाती है। शेष 25 प्रतिशत राशि हितग्राही को अंशदान के रूप में देनी होती है। योजना में 7 वर्षों तक 5 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति अनुदान का भी लाभ दिया जाता है। इस संबंध में उप संचालक ने बताया कि योजना के लिए पशुपालक के पास कम से कम 5 पशु और एक एकड़ कृषि भूमि होना आवश्यक है। पशुओं की संख्या में वृद्धि होने पर उसी के अनुपात में कृषि भूमि का निर्धारण किया जाता है। योजना की एक इकाई में 5 भैंस होने पर 4 लाख 25 हजार रुपए तथा 5 शंकर नस्ल की गाय होने पर 3 लाख 82 हजार रुपए एवं देशी गाय होने पर 2 लाख 43 हजार 750 रुपए इकाई लागत निर्धारित की गई है। 10 दुधारू पशुओं के होने पर 10 भैंसों में 8 लाख 40 हजार, शंकर गाय के लिए 7 लाख 51 हजार रुपए तथा 10 देशी गाय के लिए 4 लाख 75 हजार रुपए इकाई लागत निर्धारित की गई है। इस योजना में सामान्य वर्ग के पशुपालक को परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम एक लाख 25 हजार रुपए मार्जिन मनी सहायता के रूप में दिया जाता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितग्राही को परियोजना लागत का 33 प्रतिशत अधिकतम 2 लाख रुपए मार्जिन मनी के रूप में दिया जाता है। पशुपालन विभाग के माध्यम से प्रकरण बैंकों में भेजे जाते हैं।

आरक्षक की तत्परता से रास्ता भटके मासूम को परिजनों ने पाया सकुशल और सुरक्षित

विजय मत, शहडोल

शहडोल जिले के थाना कोतवाली क्षेत्र में डायल-112 जवानों की तत्पर और संवेदनशील कार्यवाही से खेलते-खेलते घर का रास्ता भटक गए एक 03 वर्षीय मासूम को सुरक्षित उसके परिजनों से मिलाया गया। समय पर की गई इस कार्रवाई से बच्चे को सुरक्षित संरक्षण मिल सका।01 अप्रैल को राज्य स्तरीय पुलिस कंट्रोल रूम डायल-112 भोपाल को सूचना प्राप्त हुई कि थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत इतवारी मोहल्ला में एक 03 वर्षीय बालक अकेला मिला है, जो घर का रास्ता भटक गया है। पुलिस सहायता की आवश्यकता है। सूचना प्राप्त होते ही थाना कोतवाली में तैनात डायल-112 एफआरव्ही वाहन को तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। मौके पर पहुँचकर प्रधान आरक्षक बैजनाथ सिंह एवं पायलट श्री अनुराग द्विवेदी ने बालक को अपने संरक्षण में लेकर आसपास के क्षेत्र में परिजनों की तलाश एवं पूछताछ की।लगातार प्रयासों के पश्चात बालक के परिजन मिले, जिन्हें पहचान एवं सत्यापन उपरांत बालक को सुरक्षित सुपुर्द किया गया। अपने बच्चे को सकुशल पाकर परिजनों ने राहत महसूस की और डायल-112 सेवा एवं पुलिस जवानों का आभार व्यक्त किया।डायल 112 हीरोज श्रृंखला के अंतर्गत यह घटना दर्शाती है। कि मध्यप्रदेश पुलिस की डायल-112 सेवा विशेष रूप से बच्चों की सुरक्षा के लिए सदैव सजग, संवेदनशील और प्रतिबद्ध है।

समस्या 2 करोड़ के सौंदर्याकरण प्रस्ताव के बाद भी ठप काम, बाउंड्रीवाल तक सीमित रही पहल ; बदलते अफसरों के बीच नहीं बदली तस्वीर

पौंनाग तालाब फिर बजट से गायब, सालों की योजनाएं फाइलों में दफन

विजय मत, शहडोल

शहर के बीचों-बीच स्थित पौंनाग तालाब, जिसे कभी शहर के सौंदर्य और पर्यावरण संरक्षण की बड़ी परियोजना के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई थी, आज भी उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। हाल ही में नगर पालिका द्वारा प्रस्तुत बजट में इस तालाब का नाम तक शामिल नहीं किया गया, जिससे वर्षों से चल रही योजनाओं और दावों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। नगर के बाईपास रोड स्थित पौंनाग तालाब और इसके आसपास के अन्य जलस्रोतों के संरक्षण और सौंदर्याकरण को लेकर वर्ष 2016 से पहले से ही योजनाएं बनाई जा रही हैं, लेकिन आज तक यह परियोजना धरातल पर पूरी नहीं उतर सकी है। हर बार नई योजना, नए प्रस्ताव और नई उम्मीदों के साथ शुरुआत होती है, लेकिन कुछ समय बाद मामला फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है।

बजट में नहीं मिला स्थान, बढ़े सवाल

हाल ही में पेश किए गए नगर पालिका बजट में पौंनाग तालाब के सौंदर्याकरण, जीर्णोद्धार या संरक्षण को लेकर कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इससे यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या यह परियोजना अब प्राथमिकताओं से बाहर हो चुकी है। स्थानीय नागरिकों के अनुसार, जब करोड़ों रुपये की योजनाएं बनाई जा चुकी हैं, तो उन्हें बजट में स्थान न मिलना प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाता है।

2 करोड़ की योजना कागजों में सिमटी

तालाब के सौंदर्याकरण के लिए नगर पालिका द्वारा लगभग 2 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया था। इस योजना में तालाब के चारों ओर पेवर ब्लॉक, पिचिंग, रेलिंग, फाउंटेन, लाइटिंग और बैठने की सुविधाएं विकसित करने की बात कही गई थी। सूत्रों के अनुसार, इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति भी मिल चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी।

32 लाख की बाउंड्रीवाल के बाद थमा काम

तालाबों के संरक्षण के नाम पर नगर पालिका द्वारा लगभग 32 लाख रुपये खर्च कर चारों ओर बाउंड्रीवाल का निर्माण कराया गया। हालांकि, इसके बाद कोई अन्य कार्य नहीं किया गया, जिससे यह पहल अधूरी ही रह गई। बाउंड्रीवाल निर्माण के बाद भी तालाब की स्थिति में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं दिखा, बल्कि इसे यूं ही छोड़ दिए जाने के आरोप लगते रहे।

विरोध के बाद भी नहीं बदली दिशा

बाउंड्रीवाल निर्माण के दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध भी दर्ज कराया था। उनका कहना था कि केवल दीवार बनाकर तालाब को संरक्षित नहीं किया जा सकता, जब तक इसके अंदर और आसपास के क्षेत्र का समुचित विकास न हो। इसके बावजूद न तो योजना में बदलाव किया गया और न ही आगे के कार्यों को गति मिली।

बदलते अफसर, बदलती योजनाएं, वही स्थिति

पौंनाग तालाब के विकास को लेकर समय-समय पर कई रूपरेखाएं तैयार की गईं। इस दौरान कई कलेक्टर बदले, योजनाएं बदलीं और प्राथमिकताएं भी बदलीं, लेकिन तालाब की स्थिति जस की तस बनी रही। हर बार नई योजना के साथ उम्मीदें जागीं, लेकिन वे पूरी नहीं हो

14 से 18 वर्ष तक के बच्चों का खतरनाक उद्योगों एवं प्रक्रियाओं में नियोजन प्रतिबंधित

विजय मत, शहडोल

प्रदेश में 14 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों का खतरनाक उद्योगों एवं प्रक्रियाओं में नियोजन प्रतिबंधित है। श्रम विभाग द्वारा श्रम स्टार रेटिंग के तहत बाल श्रम अथवा बंधक श्रम पाये जाने की स्थिति में ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के तहत संबंधित संस्थान को शून्य अंक दिये जाने की व्यवस्था की गई है एवं इस संबंध में सभी श्रम अधिकारियों को निर्देश दिये गये है। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये है कि ऐसे संस्थान जिनमें बाल श्रमिक अथवा बंधुआ श्रमिक नियोजित नहीं किये गए है, उनमें यदि अन्य मापदण्डों की पूर्ति थोडी कम भी हो, तो उन्हें भी श्रम स्टार रेटिंग प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया जाये। इस संबंध में श्रम विभाग द्वारा वेदा पहल के अंतर्गत प्रदेश में बाल श्रम का पूरी तरह उन्मूलन कर बच्चों को शिक्षा, पुर्नवास, सुरक्षा और अवसर प्रदान करने के संबंध में नियमित रूप से प्रत्येक शुक्रवार को समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है एवं अभियोजन मामलों की कड़ी निगरानी की जा रही है। इसी प्रकार चाइल्ड हेल्प लाइन नम्बर 1098 (टोल-फ्री 24/7) पर प्राप्त शिकायतों की मॉनीटरिंग की जा रही है। उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालय द्वारा बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मामलों में जुर्माना 20 हजार रूपये से 50 हजार रूपये तथा कारावास 6 माह से 2 वर्ष तक सजा का प्रावधान है। इसी प्रकार माननीय न्यायालय द्वारा बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत अधिकतम कारावास (3 वर्ष) की सजा या अधिकतम जुर्माना 2 हजार रूपये का प्रावधान है। बंधक श्रमिकों के पुर्नवास हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना 2021 में वयस्क पुरूष बंधक श्रमिक हितग्राहियों को एक लाख रूपये की पुनर्वास सहायता तथा अनाथ बच्चों (संगठित क्षेत्र अथवा बल पूर्वक कार्य) तथा महिला बंधक श्रमिकों को दो लाख रूपये की पुनर्वास सहायता दिये जाने के प्रावधान हैं वहीं शारिरिक शोषण अथवा मानव तस्करी से पीडितों को तीन लाख रूपये पुनर्वास सहायता दिये जाने के प्रावधान है। प्रत्येक जिले में बंधक श्रमिकों के पुर्नवास हेतु कार्पस फंड का गठन किया गया है।

अभिषेक आईपीएल मे 100 छक्का लगाने वाले सनराइजर्स के दूसरे खिलाड़ी बने

कोलकाता, एजेंसी

सनराइजर्स हैदराबाद के ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ मैच में अपनी पारी के दौरान चार छक्के लगाने के साथ ही एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अब अभिषेक आईपीएल में 100 से अधिक छक्के लगाने वाले सनराइजर्स के दूसरे बल्लेबाज बन गये हैं।वहीं पहले नंबर पर डेविड वार्नर हैं। अभिषेके के नाम अब 101 छक्के हैं जबकि वार्नर ने अब तक 143 छक्के लगाये हैं। अभिषेक ने पारी की शुरुआत करते हुए 21 गेंदों पर 48 रन बनाए जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे।

इसके साथ ही उन्होंने हैदराबाद की से अपना 100 छक्का लगाया। ब्लेसिंग मुजारबानी की गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने उनका कैच पकड़ा। सनराइजर्स के लिए सबसे अधिक 143 छक्के ऑस्ट्रेलिया के वार्नर ने लगाये हैं। वहीं अभिषेक 101 छक्कों के साथ दूसरे जबकि दक्षिण अफ्रीका के हेनरिक क्लासेन 89 छक्कों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। इसके अलावा न्यूजीलैड के केन विलियमसन 64 छक्कों के साथ चौथे और ऑस्ट्रेलिया के ही ट्रैविस हेड 50 छक्कों के साथ पांचवें स्थान पर हैं।

टीमों को बढ़ाने पर विचार कर रहा बीसीसीआई अरुण धूमल

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) साल 2008 में शुरु होने के बाद से ही लगातार छाया हुआ है। यहां तक कि आज आईपीएल दुनिया में सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है। इसके मैचों का प्रसारण दूनिया भर में होता है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) की सबसे अधिक कमाई आईपीएल से ही होती है। ऐसे में बोर्ड अब इसमें टीमें बढ़ाने पर विचार कर रहा है। आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल के अनुसार बोर्ड टीमों की संख्या बढ़ाने का कोई भी फैसला, टूर्नामेंट की गुणवत्ता से समझौता करते हुए नहीं लेगा।

धूमल ने कहा, टीम बढ़ाने का फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि इसके लिए कितना समय मिलता है। निवेशकों की इसमें कितनी रुचि है क्योंकि आईपीएल में निवेश पर असाधारण रिटर्न मिल रहा है। मैचों की संख्या बढ़ाने के पहले कई बातों का ध्यान रखना होता है। साथ ही कहा कि अगर इस लीग को नियमित रूप से आयोजित किया जाना है, तो नई व्यवस्था होगी। आईसीसी कार्यक्रम में कम द्विपक्षीय मैच रखने होंगे। तभी लीग क्रिकेट बढ़ सकता है।

साथ ही कहा कि जब बोर्ड ने प्रसारण अधिककार 48,390 करोड़ रुपए में बेचे थे, तो योजना यह थी कि धीरे-धीरे मैचों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके अनुसार साल 2023 और 2024 में 74 मैच, 2025 और 2026 में 84 मैच, और अंत में साल 2027 तक 94 मैच खेले जाने थे पर ये योजना अभी रुकी हुई है। साल 2026 में भी 74 मैच ही खेले जाएंगे। इसके पीछे को कारण आईसीसी का मौजूदा भविष्य दौरा कार्यक्रम (एफटीपी) है, जो अप्रैल 2027 तक चलेगा, इससे मैचों के बीच बहुत कम खाली समय मिलता है।

धूमल ने आईपीएल के विस्तार को लेकर कहा, लीग को 74 से 94 मैचों तक ले जाने के लिए हमें एक बड़ी विंडो की जरूरत है। ज़्यादातर अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर पहले से ही बुक है। मार्च के बीच से मई के आखिर तक का समय ही हमारे पास सीमित उपलब्ध है। वहीं जून में बारिश शुरु हो जाती है। तब र्नामेंट को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।

अगर हम मौजूदा विंडो में ही 74 से 94 मैच करवाने की कोशिश करेंगे तो हमें अधिक डबल-हेडर करवाने पड़ेंगे। जो कि प्रसारण कर्ता के लिए फायदे का सौदा नहीं होते। हमें सभी के हितों का ध्यान रखना होता है। इसीलिए हमने अब तक 74 मैच ही रखे हैं।

अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम पर भड़के केरल के खेल मंत्री?

मलप्पुरम, एजेंसी

केरल के खेल मंत्री वी अब्दुरहीमान ने कहा कि अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम ने पैसे लेने के बावजूद यहां मैच खेलने के लिए नहीं आकर राज्य को धोखा दिया। अब्दुरहीमान ने कहा कि वह वास्तव में चाहते थे कि अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम और लियोनल मेसी केरल आएं और राज्य में एक मैच खेलें।उन्होंने एक टीवी चैनल से कहा, इसके लिए मैंने कई बार बातचीत की थी। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टीम को देने के लिए 250 करोड़ रुपये की धनराशि जुटाने के लिए प्रायोजक ढूंढना आसान काम नहीं था। अब्दुरहीमान ने कहा, लेकिन पैसे मिलने के बावजूद अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम ने हमें धोखा दिया। हमें उनसे ऐसे विश्वासघात की उम्मीद नहीं थी। वादा करने के बावजूद उसकी टीम यहां नहीं आई।

केरल के खेल मंत्री ने कहा कि जब उन्होंने इस संबंध में पूछताछ की तो पता चला कि अर्जेंटीना ने पांच अन्य देशों के साथ भी ऐसा ही किया था। उन्होंने उन देशों से पैसे तो लिए लेकिन वहां खेलने नहीं गए। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम के खिलाफ मामला दर्ज करना होगा और उन्हें हमें मुआवजा देना होगा।उन्होंने कहा कि राज्य अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम का बेसब्री से इंतजार कर रहा था।

अंगक्रिश, उनादकट ऑरेंज व पर्पल कैप की दौड़ में शीर्ष पर पहुंचे

मुम्बई । कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों हार का सामना करना पड़ा है पर इस मैच में आक्रामक बल्लेबाजी करने वाले उसके बल्लेबाज अंगक्रिश रघुवंशी ऑरेंज कैप की रैस में अब सबसे आगे हो गये हैं। वहीं पर्पल कैप की दौड़ में सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाज जयदेव उनादकट नंबर एक पर पहुंच गये हैं। 19वें सत्र में लगातार दो अर्धशतक लगाने वाले केकेआर के रघुवंशी ने अब तक सबसे अधिक रन बनाये हैं। वहीं सनराइजर्स के कप्तान ईशान किशन एक बार फिर दूसरे स्थान पर रहे। पर्पल कैप की बात करें तो सनराइजर्स के जयदेव उनादकट नंबर एक पर हैं।

अंगक्रिश ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ आईपीएल 2026 के अपने पहले ही मुकाबले में 51 रनों की पारी खेलने के बाद दूसरे मैच में सराइजर्स के खिलाफ 52 रन बनाए। अब उनके नाम 2 मैचों में सबसे अधिक 103 रन हो गए हैं, जो उन्होंने 51.50 की औसत और 177.59 के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं।

अभिषेक पर आचार संहिता उल्लंघन के लिए जुर्माना लगा

कोलकाता। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में आचारसंहिता उल्लंघन के लिए सनराइजर्स हैदराबाद के आक्रामक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पर जुर्माना लगा है। अभिषेक पर जुर्माने के साथ ही उनके खाते में एक नकारात्मक अंक भी दर्ज किया गया है। अभिषेक ने कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ मैच में 21 गेंदों पर तेजी से 48 रन बना दिये। इस दौरान अभिषेक ने चार चौके और इतने ही छक्के लगाये। वह ब्लेसिंग मुजरबानी की गेंद पर कैच आउट हुए और माना जा रहा है इसी को लेकर हुए विवाद में माना जा रहा है कि उनपर आचारसंहिता उल्लंघन के लिए जुमाना लगा है। अभिषेक का कैच वरुण चक्रवर्ती ने पकड़ा पर ये स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था।

फुटबॉल विश्वकप: फाइनल देखने देने होंगे 10 लाख रुपए से ज्यादा

वाशिंगटन, एजेंसी

फीफा विश्वकप 2026 के फाइनल मुकाबले के टिकटों की कीमत 10 लाख रुपये से भी ज्यादा पहुंच गई है, जो हाल ही में हुए टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के टिकट से करीब 13 गुना अधिक है। डायनामिक प्राइसिंग सिस्टम के कारण टिकटों की कीमत लगातार बढ़ रही है, जिससे आम फैंस के लिए मैच देखना मुश्किल होता जा रहा है। वहीं, भारी डिमांड और सीमित उपलब्धता ने कीमतों को और बढ़ा दिया है, जिससे यह टूर्नामेंट अब तक का सबसे महंगा वर्ल्ड कप बन सकता है।

फीफा विश्वकप 2026 का आगाज 11 जून से होने जा रहा है। इस बार यह टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की संयुक्त मेजबानी में होगा। हालांकि, फीफा ने फैंस को बड़ा झटका दिया है। फीफा ने विश्वकप की 48 टीमों के तय हो जाने के बाद फाइनल के लिए टिकट की अधिकतम कीमत बढ़ाकर 10,990 अमेरिकी डॉलर यानी 10.28 लाख भारतीय रुपये कर दी हैं।

दिसंबर में टूर्नामेंट के ड्रॉ के बाद जब फीफा ने टिकट बेचे थे तब श्रेणी एक के टिकट की कीमत 8,680 यूएस डॉलर थी यानी 8.12 लाख रुपये। यह दाम हाल ही में अहमदाबाद में हुए टी20 विश्वकप के फाइनल की टिकट की दाम से लगभग 13 गुना ज्यादा है। आइए जानते हैं पूरा मामला...

न्यू जर्सी के ईस्ट रदरफोर्ड स्थित मेटलाइफ स्टेडियम में 19 जुलाई को होने वाले फाइनल मैच के लिए फीफा के श्रेणी दो के टिकटों की कीमत 7,380 अमेरिकी डॉलर यानी 6.90 लाख रुपये कर दी गई है, जो पहले 5,575 अमेरिकी डॉलर थी यानी कि 5.22 लाख रुपये। इसी तरह से श्रेणी तीन के टिकटों की कीमत 5,785 यूएस डॉलर (5.41 लाख भारतीय रुपये) कर दी गई है जो पहले की कीमत से 4,185 डॉलर यानी 3.92 लाख रुपये अधिक है।

पहले श्रेणी तीन के टिकटों की कीमत एक लाख से ज्यादा थी

टी20 विश्वकप 2026 फाइनल के टिकट का दामअहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आठ मार्च 2026 को हुए टी20 विश्वकप 2026 फाइनल के आधिकारिक टिकटों की शुरुआती कीमत दो हजार रुपये रखी गई थी। प्रीमियम सीटों की कीमत 20 हजार रुपये से लेकर 25 हजार रुपये तक थी, जबकि हॉस्पिटैलिटी सूट्स के टिकट 50 हजार रुपये से 75 हजार रुपये के बीच थे।अगर टी20 विश्वकप फाइनल के अधिकतम 75 हजार रुपये से भी फीफा विश्वकप फाइनल के अधिकतम दाम की तुलना हो तो यह 13+ गुना ज्यादा है। हालांकि, रीसेल मार्केट में टिकटों की कीमतें आसमान छू रही थीं, जहां एक सीट के लिए दो से तीन लाख तक वसूले जाने की खबरें सामने आईं थीं। फीफा विश्वकप 2026 के आम टिकटों के दाम भी टी20 विश्वकप 2026 के आम टिकटों के दाम से ज्यादा हैं।

टाइगर ने राइडर कप से नाम वापस लेने के साथ ही खेल से ब्रेक लिया

न्यूयार्क, एजेंसी

विश्व के नंबर एक दिग्गज रहे गोल्फर टाइगर वुड्स फिट नहीं होने के कारण राइडर कप गोल्फ टूर्नोमेंट में भाग नहीं लेंगे। वुड्स ने खराब सेहत का हवाला देते हुए खेल से ब्रेक लेने की भी घोषणा कर दी है। वुड्स ने कहा है कि वह इलाज के लिए विदेश जा रहे हैं।

कप्तानी ठुकरा दी

वह पिछले कुछ समय से गोल्फ से जुड़ी गतिविधियों से दूर थे पर गुरुवार को उन्होंने औपचारिक रूप से राइडर कप की कप्तानी ठुकरा दी साथ ही कहा कि वह इलाज के लिए विदेश जा रहे हैं। उन्हें अदालतन ने इलाज के लिए देश से बाहर जाने की अनुमति भी दे दी है। वुड्स को पिछले सप्ताह नशे में गाड़ी चलाने के संदेह के कारण गिरफ्तार किया गया था हालांकि कुछ घंटे बाद ही उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था। इसी कारण उन्हें विदेश जाने से पहले अदालत से अनुमति लेनी पड़ी हैं।

निजता बनाना

वुड्स ने एक बयान जारी कर कहा कि वह 'इलाज कराने और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए' अनिश्चित काल के लिए खेल से दूर जा रहे हैं। उनके वकील डगलस डंकन ने दायर एक याचिका में न्यायाधीश से वुड्स को उपचार के लिए विदेश जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि वुड्स को इलाज के लिए विदेश इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि अमेरिका में उनके लिए अपनी निजता बनाये रखना संभव नहीं है।

व्यापार

कच्चे तेल की कीमतें 100 से 120 डॉलर प्रति बैरल के दायरे में आईं

नई दिल्ली, एजेंसी

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के चलते वैश्विक तेल आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ा है, जिसका सीधा असर भारत पर भी देखने को मिल रहा है। भारतीय ऑयल बास्केट की औसत कीमत मार्च 2026 में 113.49 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गई, जो पिछले चार वर्षों का उच्चतम स्तर है। इससे पहले रसिया-यूक्रेन वार के दौरान मार्च 2023 में यह 112.87 डॉलर तक गई थी। रविवार को ओपेक देशों की बैठक होगी। इसमें ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। 1 अप्रैल को भारतीय रिफाइनरियों के लिए कच्चे तेल की कीमत 120.84 डॉलर प्रति बैरल दर्ज की गई, जबकि ब्रेंट क्रूड करीब 107 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। फिलहाल अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 100 से 120 डॉलर प्रति बैरल के दायरे में बनी हुई हैं।

तेल संकट गहराया, भारत में कीमतें चार साल के उच्च स्तर पर पहुंचीं

दवाओं पर भारी टैरिफ का खतरा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेटेंट दवाओं के आयात को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए नया कार्यकारी आदेश जारी किया है, जिससे वैश्विक फार्मा उद्योग में हलचल मच गई है। अमेरिका में दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अहम कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इस आदेश के तहत उन फार्मा कंपनियों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाया जा सकता है, जो अमेरिकी सरकार के साथ "मोस्ट फेवर्ड नेशन" प्राइसिंग समझौता नहीं करेंगी। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, जो कंपनियां अमेरिका में पेटेंट दवाओं और उनके कच्चे माल का उत्पादन शुरू करेंगी और कीमत समझौते पर सहमत होंगी, उन्हें टैरिफ से छूट दी जाएगी। वहीं, जो कंपनियां उत्पादन तो शुरू करेंगी लेकिन समझौता नहीं करेंगी, उन पर शुरुआती 20 प्रतिशत टैरिफ लगेगा, जो चार वर्षों में बढ़कर 100 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। कंपनियों को समझौते के लिए समय भी दिया गया है, बड़ी कंपनियों को 120 दिन और अन्य को 180 दिन। बताया गया है कि सरकार पहले ही कई बड़ी कंपनियों के साथ समझौते कर चुकी है। इस फैसले के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया गया है, क्योंकि सरकार का मानना है कि दवाओं के आयात पर अत्यधिक निर्भरता जोखिम पैदा कर सकती है।

सभी उड़ानों में 60 फीसदी सीटें बिना शुल्क उपलब्ध

नई दिल्ली । नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने घोषणा की है कि 20 अप्रैल से सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में कम से कम 60 प्रतिशत सीटें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध कराई जाएंगी। इसका उद्देश्य यात्रियों को न्यायसंगत सुविधा देना और सीट आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। डीजीसीए ने निर्देश दिया है कि विमानन कंपनियों को अपनी सीट आवंटन नीतियों को पारदर्शी बनाना होगा। सभी शुल्क रहित सीटों की उपलब्धता और लागू शर्तें बुकिंग वेबसाइट या ऐप पर स्पष्ट रूप से दिखानी होंगी। इसके अलावा, खेल उपकरण, संगीत वाद्य यंत्र जैसी वैकल्पिक सेवाओं के लिए सभी शुल्क और किसी भी नुकसान की स्थिति में जिम्मेदारी की शर्तें भी स्पष्ट रूप से यात्रियों को उपलब्ध कराई जाएंगी। वर्तमान में केवल लगभग 20 प्रतिशत सीटें मुफ्त चयन के लिए उपलब्ध हैं। बाकी सीटों के लिए यात्री 200 से 2,100 तक का शुल्क देते हैं।

युद्ध का दिख रहा सीधा असर: रुपया गिरा महंगाई बढ़ेगी ! आम आदमी पर पड़ेगा असर

नई दिल्ली, एजेंसी

पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने से पहले ही भारत की अर्थव्यवस्था में कमजोरी के संकेत दिखाई देने लगे थे। जैसे ही ईरान से जुड़े तनाव बढ़े और डॉलर सुरक्षित निवेश के रूप में मजबूत हुआ, रुपये पर दबाव और तेज हो गया। पिछले एक साल में एशिया की सबसे कमजोर करेंसी रहे रुपये ने 95 प्रति डॉलर का स्तर पार कर 95.12 का रिकॉर्ड निचला स्तर छू लिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि युद्ध केवल एक ट्रिगर है, जबकि असली कमजोरी देश के अंदर की आर्थिक स्थिति से जुड़ी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों की डॉलर पोजिशन 100 मिलियन तक सीमित करने का फैसला बाजार को भरोसा दिलाने के बजाय उल्टा संकेत दे गया। निवेशकों ने इसे इस रूप में देखा कि आरबीआई के पास रुपये को संभालने के पारंपरिक उपाय अब पर्याप्त नहीं रह गए हैं। इससे सट्टेबाजों को मौका मिला और रुपये पर दबाव और बढ़ गया। रिपोर्ट के अनुसार किसी भी केंद्रीय बैंक के सामने यह चुनौती होती है कि वह एक साथ मुद्रा को स्थिर रखने और ब्याज दरों को नियंत्रित करने दोनों काम नहीं कर सकता। आरबीआई लंबे समय तक इस संतुलन को बनाए रखने की कोशिश करता रहा।

गवर्नर संजय मल्होत्रा के कार्यकाल में ब्याज दरों में कटौती कर निवेश को बढ़ावा दिया गया और रुपये को कमजोर होने दिया गया ताकि निर्यात को सहारा मिल सके। लेकिन तेल की कीमतों में तेजी के बाद यह रणनीति दबाव में आ गई है।

अब आरबीआई के सामने ग्रोथ और मुद्रा स्थिरता के बीच कठिन चुनाव है। रुपये की कमजोरी का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ता है। खासकर तेल की कीमतें बढ़ने से पेट्रोल, डीजल और गैस महंगे होते हैं, जिसका असर ट्रांसपोर्ट, खाद और खाने-पीने की चीजों तक पहुंचता है। इससे जीवन यापन की लागत बढ़ जाती है।

फ्लाइट सीट चयन नियम पर 60 फीसदी मुफ्त सीट वाला आदेश स्थगित

- एयरलाइंस की आपत्तियों के बाद फैसले पर रोक, किराया संरचना और संचालन पर असर की समीक्षा जारी

नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्र सरकार ने एयरलाइंस के लिए हर उड़ान में कम से कम 60 प्रतिशत सीटें बिना अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध कराने के अपने प्रस्ताव को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यह निर्णय डायरेक्टोरेट जनरल आफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) को भेजे पत्र में साझा किया। मंत्रालय के अनुसार फेडरेशन आफ इंडियन एयरलाइंस और अकासा एयर सहित विभिन्न हितधारकों से मिले सुझावों के आधार पर इस नीति की समीक्षा की गई। एयरलाइंस ने इस प्रावधान के परिचालन और व्यावसायिक प्रभाव, किराया ढांचे में संभावित बदलाव और मौजूदा डिरेगुलेटेड सिस्टम से टकराव जैसे मुद्दे उठाए। इन परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने कहा कि विस्तृत अध्ययन पूरा होने तक इस आदेश को लागू नहीं किया जाएगा। वर्तमान में एयरलाइंस लगभग 20 प्रतिशत सीटें मुफ्त चयन के लिए देती हैं, जबकि बाकी सीटों के लिए 200

जम्मू संभाग के 100 स्कूलों में हर्बल गार्डन स्थापित करने की मंजूरी

जम्मू (ईएमएस)। आयुष मंत्रालय के तहत नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड ने जम्मू संभाग में 100 स्कूलों में हर्बल गार्डन स्थापित करने के महत्वाकांक्षी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस परियोजना के लिए कुल 53 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस पहल के तहत संभाग के प्रत्येक जिले से 10-10 स्कूलों को चयनित किया गया है। ये हर्बल गार्डन छात्रों के लिए जीवंत शिक्षण केंद्र के रूप में विकसित होंगे, जहां वे औषधीय पौधों की पहचान, खेती और उपयोग संबंधी जानकारी सीख सकेंगे। इसका उद्देश्य स्कूल शिक्षा प्रणाली में पारंपरिक औषधीय ज्ञान और प्रकृति के प्रति

समाधान 25,000 करोड़ की मेगा परियोजना, कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग किया जाएगा

भारत में पहली स्वदेशी गैसीकरण परियोजना के जमीन पट्टे पर समझौता हुआ

नई दिल्ली, एजेंसी

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव व वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में उतार-चढ़ाव के दौर में भारत में ऊर्जा सुरक्षा के लिए पहली स्वदेशी गैसीकरण परियोजना के जमीन पट्टे पर समझौता हुआ। भारत कोल गैसिफिकेशन ऐंड कैमिकल लिमिटेड (बीसीजीसीएल) और महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) ने समझौता किया। इसके तहत ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले के लखनपुर में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने की पहली स्वदेशी परियोजना के लिए समझौता हुआ। इससे आयात पर निर्भरता भी घटेगी। सूत्रों के अनुसार इस परियोजना की क्षमता 2,000 टन प्रतिदिन (टीपीडी) है। परियोजना के लिए अनुमानित निवेश करीब 25,000 करोड़ रुपये है। यह समझौता महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसमें भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग किया जाएगा। कोयला गैसीकरण तकनीक कोयले को सिंथेसिस गैस (सिनगैस) में बदलती है। फिर सिनगैस से अमोनिया, मेथनॉल, यूरिया, हाइड्रोजन, सिंथेटिक प्राकृतिक गैस (एसएनजी), पेट्रोकेमिकल्स और तरल ईंधन सहित विभिन्न मूल्यवर्धित उत्पाद बनाए जा सकते हैं। इस क्रम में लखनपुर परियोजना विशेष रूप से अमोनियम नाइट्रेट के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करेगी। यह प्रमुख औद्योगिक रसायन है और इसका उपयोग उर्वरकों और खनन में व्यापक रूप से होता है। दरअसल, कोयला

मंत्रालय ने ऊर्जा उत्पादों के आयात को कम करने के लिए सात कोयला परियोजनाओं के लिए 64,000 रुपये मंजूर किए हैं। इन सात परियोजनाओं में से एक लखनपुर परियोजना है। इस क्रम में सात परियोजनाओं में से चार महाराष्ट्र, दो ओडिशा और एक पश्चिम बंगाल में होगी। लखनपुर परियोजना एमसीएल की 350 एकड़ से अधिक भूमि पर स्थापित की जाएगी। दरअसल, कोयलना मंत्रालय ने हाल ही में नीति में बदलाव किए हैं।

मुख्यमंत्री ने उज्जैन में किया 'महाकालः द मास्टर ऑफ टाइम' का उद्घाटन, बोले-

उज्जैन धर्म के साथ विज्ञान की भी नगरी, यहां से होती थी काल गणना

विजय मत, ब्यूरो उज्जैन

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि विज्ञान, गणित और खगोल ज्ञान की प्राचीन राजधानी रहा है। यहां सदियों पहले सूर्य की छाया से समय मापने की विधि विकसित हुई और नक्षत्रों की सटीक गणना की जाती थी। उन्होंने कहा कि जब दुनिया समय को समझने की शुरुआत कर रही थी, तब उज्जैन के विद्वान काल गणना के मानक स्थापित कर चुके थे। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 'महाकालः द मास्टर ऑफ टाइम' के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री ने उज्जैन को विज्ञान नगरी के रूप में विकसित करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ 2028 उज्जैन को वैश्विक पहचान दिलाने का अवसर बनेगा और यहां आने वाले श्रद्धालु धार्मिक महत्व के साथ वैज्ञानिक विरासत को भी समझ सकेंगे।

उज्जैन काल गणना का केंद्र रहा, प्राचीन विज्ञान की अद्भुत परंपरा

मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन प्राचीन भारत में काल गणना और खगोल विज्ञान का प्रमुख केंद्र था। यहां कर्क रेखा के आधार पर समय और नक्षत्रों की गणना की जाती थी। उन्होंने बताया कि ग्रीनविच से पहले शून्य देशांतर रेखा उज्जैन से होकर गुजरती थी। जब पश्चिमी देशों में खगोल विज्ञान विकसित नहीं हुआ था, तब यहां के विद्वान सटीक गणनाएं कर रहे थे। यह परंपरा भारतीय ज्ञान प्रणाली की वैज्ञानिकता को दर्शाती है और आज भी आधुनिक विज्ञान के लिए प्रेरणास्रोत बनी हुई है।

उज्जैन को विज्ञान नगरी बनाने की दिशा में बड़े कदम

मुख्यमंत्री ने उज्जैन विज्ञान केंद्र के लोकार्पण को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। लगभग 15 करोड़ रुपये की लागत से बने इस केंद्र में विज्ञान गैलरी, नवाचार कक्ष, छात्र गतिविधि क्षेत्र और वैज्ञानिक प्रदर्शनी जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं। उन्होंने कहा कि यह केंद्र विद्यार्थियों और शोधार्थियों को विज्ञान के प्रति आकर्षित करेगा। उज्जैन को विज्ञान नगरी के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है, जिससे नई पीढ़ी को वैज्ञानिक दृष्टिकोण और शोध के अवसर मिल सकें तथा प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का समन्वय मजबूत हो सके।

सिंहस्थ 2028 के लिए 700 करोड़ से अधिक के विकास कार्य

मुख्यमंत्री ने सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर 700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं का भूमि-पूजन किया। इसमें 4-लेन बायपास सड़क सहित कई अधोसंरचनात्मक विकास कार्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है और इसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में बेहतर यातायात, सुविधा और प्रबंधन सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। यह विकास कार्य उज्जैन को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के साथ स्थानीय लोगों को भी दीर्घकालिक लाभ पहुंचाएंगे और शहर की समग्र संरचना को मजबूत करेंगे।

विज्ञान और आध्यात्म का अनूठा समन्वय है उज्जैन

कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उज्जैन वह स्थान है जहां विज्ञान और आध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा में विज्ञान और आध्यात्म एक-दूसरे के पूरक रहे हैं। नई शिक्षा नीति के माध्यम से इस परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

श्रद्धांजलि...

विजय मत, ब्यूरो उज्जैन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन प्रवास के दौरान स्व. गुरकीरत सिंह मनोचा के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। विगत दिवस कनाडा में दुखद दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शासन प्रदेशवासियों के सुख-दुख में साथ है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार और मध्यप्रदेश शासन के प्रयासों से स्व. मनोचा का पार्थिव शरीर कनाडा से भारत लाया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बाबा महाकाल से स्व. मनोचा परिवार को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के साथ प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने भी स्व. मनोचा को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

मप्र में एआई के जरिए होगी आंगनबाड़ी केंद्रों की मॉनिटरिंग

प्रदेश के बालाघाट जिले में पहली बार हो रहा तकनीक का उपयोग

विजय मत, भोपाल

आज का दौर टेक्नोलॉजी और एआई का है। हर क्षेत्र में तेजी के साथ तकनीक का उपयोग हो रहा है। जिसके फायदे और नुकसान दोनों हमें देखने मिलते हैं। इसी के मद्देनजर मप्र में एआई के जरिए आंगनबाड़ी केंद्रों की मॉनिटरिंग की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। प्रदेश का बालाघाट पहला ऐसा जिला है, जहां एआई के जरिए आगनबाड़ी केंद्रों की मॉनिटरिंग की जा रही है। बच्चों की उपस्थिति और टीएचआर (टेक होम राशन) वितरण में पारदर्शिता को लेकर अनोखा प्रयोग किया गया है। कलेक्टर के निर्देशन में युवाओं ने यह राइज बाल गिनती एप बनाया है। बच्चों की अनौपचारिक शिक्षा के साथ-साथ उनके शारीरिक व मानसिक विकास की नींव तैयार करने की मंशा को लेकर शासन द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। बच्चों के पूरे विकास की परिकल्पना को लेकर काम कर रहे इन केन्द्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करते हुए इन्हें और अधिक पारदर्शी बनाने को लेकर बालाघाट में एक इनोवेशन शुरू किया गया है। हम कह सकते हैं कि बालाघाट मध्य प्रदेश का वह पहला जिला है, जहां आंगनबाड़ी केन्द्रों में एआई के जरिए निगरानी रखी जाएगी। यहां पर कलेक्टर के निर्देशन में एक ऐसा एप तैयार किया गया है, जो आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अपनी नजर बनाए रखेगा।

सुबह 11 बजे एप के जरिए अपलोड करनी होगी तस्वीर

खास बात यह कि इस एप को कलेक्टर मृणाल मीणा के निर्देशन में बालाघाट के ही युवाओं ने तैयार किया है। जो कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में पारदर्शिता लाने को लेकर तैयार किया गया है। कलेक्टर मृणाल मीणा ने बताया कि यहां के युवाओं ने एक एप तैयार किया है, जिसका नाम राइज बाल गिनती है। यह एप आंगनबाड़ी केन्द्रों में निगरानी रखेगा, जो सीधे जिला प्रशासन के कंट्रोल में होगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्रों में सुबह 11 बजे इस एप के माध्यम से एक तस्वीर अपलोड की जाएगी। जिससे बच्चों की दैनिक उपस्थिती दर्ज होगी। कुपोषित बच्चों की सीधी निगरानी जिला प्रशासन रख सकेगा।

न्यूज इन शॉर्ट

मुख्यमंत्री का उज्जैन के श्री बालाजी श्याम सरकार मंदिर में सम्मान

विजय मत, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का शुक्रवार को उज्जैन प्रवास के दौरान श्री बालाजी श्याम सरकार मंदिर में सम्मान किया गया। इस अवसर पर अनेक श्रद्धालु उपस्थित थे। बालाजी श्याम सरकार मंदिर में महंत मनीष पारिख ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव का अंगवस्त्रम से सम्मान किया। प्रारंभ में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भगवान हनुमान जी, श्री खाटू श्याम जी और देवी दुर्गा मां के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश और देश के नागरिकों के कल्याण की कामना की।

आलोक नागर और राजेश भट बने राज्य सूचना आयुक्त

विजय मत, भोपाल। राज्य शासन ने मप्र राज्य सूचना आयोग में दो सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कर दी है। 2 अप्रैल को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार आलोक नागर और राजेश भट को राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। जानकारी के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग ने दो महीने पहले राज्य सूचना आयोग में आयुक्त के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए आवेदन बुलाए थे। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने रिक्त पदों पर दो सूचना आयुक्त आलोक नागर और राजेश भट की नियुक्ति की है। इन नियुक्तियों के साथ ही आयोग में 5 सूचना आयुक्त हो गए हैं। हालांकि अभी भी सूचना आयुक्तों की पांच पद खाली हैं। आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त तक आयुक्तों के 11 पद हैं।

भोपाल के छोटे तालाब के वजूद पर संकट, 7 विभागों को नोटिस जारी

विजय मत, भोपाल। छोटे तालाब में बढ़ते प्रदूषण, अतिक्रमण और सीवेज मिलने को लेकर दायर याचिका पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सख्त रुख अपनाया है। तालाब के संरक्षण में हो रही लापरवाही पर एनजीटी ने केंद्र और राज्य सरकार सहित सात विभागों को नोटिस जारी किया है। पर्यावरणविद् राशिद नूर खान ने याचिका में बताया गया है छोटा तालाब अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जल क्षमता खो रहा है। तालाब की सीमाओं से छेड़छाड़ कर मलबे की डंपिंग की जा रही है, इससे न केवल तालाब का आकार छोटा हो रहा है, बल्कि भूजल पुनर्भरण की क्षमता भी कम हो रही है। याचिका के साथ पेश की गई तस्वीरों से स्पष्ट है कि खुले नालों और पाइपलाइनों के जरिए बिना ट्रीटमेंट के गंदा पानी सीधे तालाब में गिर रहा है।

मध्यप्रदेश पुलिस की अवैध हथियारों की तस्करी के विरूद्ध सख्त कार्रवाई

विगत तीन सप्ताह में 52 अवैध हथियार जब्त

विजय मत, भोपाल

मध्यप्रदेश पुलिस अवैध हथियारों की तस्करी एवं अपराध नियंत्रण के विरुद्ध प्रदेशभर में लगातार सख्त और प्रभावी कार्रवाई कर रही है। इसी कार्यवाही के तहत विगत तीन सप्ताह के दौरान विभिन्न जिलों से 52 अवैध हथियार जब्त कर तस्करों को गिरफ्तार किया है।

इंदौर... जिले के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र से पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (टेलीग्राम एवं इंस्टाग्राम) के माध्यम से ग्राहकों से संपर्क स्थापित कर अवैध हथियारों की आपूर्ति करने वाले एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 06 देशी पिस्टल एवं 04 जिंदा कारतूस बरामद किए है। वहीं, इंदौर ग्रामीण के थाना मानपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 04 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 पिस्टल जब्त की है। इस प्रकार इन दोनों कार्रवाइयों में पुलिस ने कुल 16 अवैध हथियार जप्त किये है।

खरगोन... जिले में थाना गोगावां पुलिस ने अंतर्राज्यीय हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए उत्तरप्रदेश एवं हरियाणा के आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 देशी पिस्टल एवं 05 देशी कट्टे (कुल 15 अवैध हथियार) तथा एक मोटरसाइकिल जब्त की। इसके अलावा थाना गोगावां एवं थाना भीकनगाँव पुलिस ने अलग-अलग कार्रवाई करते हुए 03 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 08 देशी पिस्टल एवं 02 मोटरसाइकिल जब्त की हैं। इस प्रकार खरगोन जिले में कुल 23 अवैध हथियार जब्त किए गए हैं।

बड़वानी... थाना निवाली में पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक अवैध हथियार तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 07 देशी पिस्टल की है।

जबलपुर... जिले में क्राइम ब्रांच एवं थाना पाटन पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के कारोबार में लिप्त 02 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 04 देशी पिस्टल, 08 कारतूस, 03 मोबाइल फोन एवं एक कार जब्त की है। आरोपियों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है।

बुरहानपुर... थाना खकनार में अंतर्राज्यीय अवैध हथियार तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए पंजाब के 02 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 02 हस्तनिर्मित पिस्टल जब्त की हैं।

इन सभी कार्रवाइयों से स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश पुलिस अवैध हथियारों की तस्करी के विरुद्ध सतत सतर्कता एवं दृढ़ता के साथ कार्य कर रही है। पुलिस की त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई के चलते अपराधियों के विरुद्ध कठोर कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे प्रदेश में कानून-व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ हो रही है।

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन "महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम" में विशेषज्ञों ने रखे विचार

विश्व काल-गणना के केंद्र के रूप में उज्जैन की भूमिका पर हुई वैश्विक चर्चा

विजय मत, ब्यूरो उज्जैन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में महाकाल की पावन धरा उज्जैन में शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन महाकालः द मास्टर ऑफ टाइम हुआ। देश-विदेश के प्रख्यात खगोलविदों, वैज्ञानिकों और शीर्षस्थ विद्वानों ने भारतीय काल-गणना की वैज्ञानिकता और उसकी प्राचीन श्रेष्ठता पर गहन मंथन किया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य उज्जैन की गौरवशाली पहचान को वैश्विक पटल पर पुनः स्थापित करना है। उज्जैन नगरी युगों तक विश्व के प्रधान मध्याह्न रेखा (प्राइम मेरिडियन) और काल-गणना का केंद्र रही है। विद्वानों ने एक स्वर में यह आह्वान किया कि अब समय आ गया है जब हम समय की वैश्विक अवधारणा के %भारतीयकरण% की ओर बढ़ें और अपनी उस वैज्ञानिक विरासत को जीवंत करें, जो सदियों तक मानवता के लिए समय का बोध कराती रही है। सम्मेलन के प्रथम सत्र का मुख्य विषय समय क्या है? इसका मापन कैसे हुआ तथा प्रधान मध्यान्ह (मेरेडियन) रेखा के रूप में उज्जैन का महत्व रहा। सत्र का संचालन करते हुए आईआईटी गुवाहाटी के प्रो. तडीकोंडा वेंकट भारत ने समय के मूल स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्राचीन भारत काल-गणना के क्षेत्र में संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शक था। कालांतर में सांस्कृतिक संक्रमण के कारण हमारा यह अमूल्य ज्ञान पाश्चात्य पद्धतियों के अधीन हो गया। अब समय की मांग है कि हम आधुनिक विज्ञान और शोध के माध्यम से अपनी विरासत का पुनरुद्धार करें। राज्यसभा की एस. राधाकृष्णन पीठ के इतिहासविद् डॉ. एम.एल. राजा ने गर्व के साथ भारत को काल-गणना का देवता निरूपित किया। उन्होंने कहा कि पाश्चात्य जगत जिस कालखंड की सूक्ष्मता को समझने का प्रयास कर रहा है, वह भारतीय मनीषियों के लिए हजारों वर्ष पूर्व भी प्रत्यक्ष सत्य था।

मदिरा दुकानों के लिये गठित मंत्री-मंडलीय समिति की हुई बैठक

मदिरा दुकानों के संचालन के लिये बनेगा निगम-मंडल

विजय मत, भोपाल। आबकारी विभाग के लिए गठित मंत्री-मंडलीय समिति की वर्चुअल बैठक में 12 दौर की नीलामी प्रक्रिया के बाद शेष बची दुकानों की स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि नीलामी के बाद शेष 489 दुकानों के संचालन के लिए आबकारी विभाग स्वयं एक निगम/मंडल गठित कर इन दुकानों के संचालन की संभावना पर विचार करेगा। मंत्री-मंडल समिति में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर अमित राठौर और आयुक्त आबकारी दीपक कुमार सक्सेना मौजूद रहे।

दमोह के डायल-112 हीरोज... सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 03 को पहुँचाया अस्पताल

विजय मत, ब्यूरो दमोह

दमोह जिले के थाना हटा क्षेत्र में डायल-112 जवानों की तत्पर एवं संवेदनशील कार्रवाई से दो मोटर साइकिल की टक्कर में गंभीर रूप से घायल तीन व्यक्तियों को समय पर अस्पताल पहुँचाकर उपचार उपलब्ध कराया गया। इस त्वरित कार्रवाई से घायलों को शीघ्र चिकित्सकीय सहायता मिल सकी।

02 अप्रैल को राज्य स्तरीय पुलिस कंट्रोल रूम डायल-112, भोपाल को सूचना प्राप्त हुई कि थाना हटा क्षेत्र अंतर्गत सेमरी फतेहपुर के पास दो मोटर साइकिल की आपसी टक्कर में 03 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं एवं तत्काल पुलिस सहायता की आवश्यकता है। सूचना प्राप्त होते ही हटा थाना क्षेत्र में तैनात डायल-112 एफआरव्ही वाहन को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। मौके पर पहुँचकर डायल-112 स्टाफ आरक्षक श्री देवेन्द्र आठिया एवं पायलट श्री श्रीराम पटेल ने दुर्घटना में घायल तीनों व्यक्तियों को तत्काल सहायता प्रदान करते हुए त्वरित राहत कार्य प्रारंभ किया गया। डायल-112 जवानों ने सभी घायलों को एफआरव्ही वाहन की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, हटा पहुँचाया, जहाँ उनका उपचार किया जा रहा है। डायल-112 की त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई से घायलों को समय पर उपचार उपलब्ध हो सका। डायल-112 हीरोज श्रृंखला के अंतर्गत यह घटना दर्शाती है कि मध्यप्रदेश पुलिस की डायल-112 सेवा आपात परिस्थितियों में आमजन की सहायता हेतु सदैव सजग, संवेदनशील एवं प्रतिबद्ध है।

3056 एलपीजी सिलेण्डर जब्त और 9 मामलों में एफआईआर की गई दर्ज

विजय मत, भोपाल

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जानकारी दी है कि मध्यप्रदेश में एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, पीएनजी और सीएनजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और सप्लाई में किसी प्रकार की रुकावट नहीं है। मंत्री राजपूत ने अपील की है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें तथा घबराहट में खरीदारी (पैनिक बाइंग) से बचें।

प्रदेश में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब तक 2250 स्थानों पर जांच की गई है, जिसमें 3056 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए हैं और 9 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा 564 पेट्रोल पंपों की जांच भी की गई, जिनमें 2 मामलों में प्रकरण दर्ज कर एफआईआर दर्ज की गई है। जिला आपूर्ति अधिकारियों और ऑयल कंपनियों के अधिकारियों को पेट्रोल पंपों की नियमित जांच के निर्देश दिए गए हैं। घरेलू गैस उपभोक्ताओं द्वारा की गई बुकिंग के अनुरूप सिलेंडरों की आपूर्ति नियमित रूप से की जा रही है। वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को भी शासन द्वारा निर्धारित प्राथमिकता क्रम के अनुसार कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सतत आपूर्ति की जा रही है। उपभोक्ताओं की मांग को देखते हुए गैस बॉटलिंग प्लांट अतिरिक्त समय तक कार्य कर रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित प्लांट और वितरकों के स्टॉक की निरंतर समीक्षा की जा रही है। प्रदेश में सभी ऑयल कंपनियों के पास पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। पेट्रोल पंपों पर किसी प्रकार की कमी नहीं है और कंपनियों के डिपो से नियमित रूप से आपूर्ति जारी है। बढ़ती मांग को देखते हुए ऑयल कंपनियों के डिपो को भी अधिक समय तक संचालित किया जा रहा है, जिससे आपूर्ति व्यवस्था को सामान्य बनाए रखा जा सके।

विजय मत एंकर इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में 10 अप्रैल तथा शेष संभागों में 15 से होगी खरीदी

समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की तैयारी पूरी, 78 लाख मीट्रिक टन है उपार्जन का लक्ष्य

विजय मत, भोपाल

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि प्रदेश में गेहूं उपार्जन के लिये इस वर्ष रिकॉर्ड 19 लाख 4 हजार किसानों ने पंजीयन कराया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3 लाख 60 हजार अधिक है। मंत्री राजपूत ने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन की सभी व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित की जा रही हैं। प्रदेश सरकार किसान हितैषी सरकार के रूप में किसानों को बेहतर लाभ दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से किसानों को इस वर्ष 2585 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य के साथ ही 40 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस

दिया जा रहा है। इससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सकेगा। उन्होंने बताया है कि इस वर्ष किसानों का पंजीकृत रकबा 41.58 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया है, जो विगत वर्ष से 6.65 लाख हेक्टेयर अधिक है। मंत्री राजपूत ने कहा कि किसानों को उपार्जन केन्द्रों पर इंतजार न करना पड़े, इसके लिए उपार्जन प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से शुरू की जा रही है। इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में 10 अप्रैल 2026 से तथा शेष संभागों में 15 अप्रैल 2026 से समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन प्रारंभ किया जाएगा।

मंत्री राजपूत ने जानकारी दी कि राजस्व विभाग द्वारा किसानों के पंजीकृत रकबे के सत्यापन का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। सत्यापन पूर्ण होने के बाद किसानों के लिए स्लॉट बुकिंग प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी, जिससे किसान अपनी उपज बिना किसी असुविधा के उपार्जन केन्द्रों पर बेच सकें। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष समर्थन मूल्य पर लगभग 77 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया था।

50 हजार जूट की गठानों का अतिरिक्त आवंटन

मंत्री राजपूत ने कहा कि एलपीजी गैस की उपलब्धता बनाए रखने और औद्योगिक उपयोग में पेट्रोलियम पदार्थों की सीमाओं के कारण बारदानों की उपलब्धता में आई संभावित कठिनाइयों का भी समाधान कर लिया गया है। भारत सरकार ने मध्यप्रदेश को 50 हजार जूट की गठानों का अतिरिक्त आवंटन किया है। साथ ही गेहूं उपार्जन के लिए एचडीपी/पीपी बैग और एक बार उपयोग होने वाले जूट बारदाने के उपयोग की अनुमति भी दी गई है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार लगातार बारदाना उपलब्धता और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा कर राज्य सरकार को सहयोग प्रदान कर रही है। प्रदेश में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए आवश्यक बारदानों की व्यवस्था उपार्जन प्रारंभ होने से पूर्व पूरी कर ली जाएगी। मंत्री राजपूत ने बताया कि जिन जिलों में भंडारण क्षमता सीमित है, वहां संयुक्त भागीदारी योजना के तहत गोदाम की क्षमता के 120 प्रतिशत तक भंडारण की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सीता शुक्ला द्वारा प्रदेश वॉच मीडिया ग्रुप, 11 प्रेस कॉम्प्लेक्स, जोन-01, एमपी नगर, भोपाल (म.प्र.) से मुद्रित एवं ई.एम.एस. 21 इंडस टाउन, होशंगाबाद रोड, मिसरोद, भोपाल (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सीता शुक्ला। प्रधान संपादक- विजय शुक्ला
(*समाचार चयन के लिए पी.आरर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार)। सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र भोपाल होगा। आर.एन.आई. क्रमांक- MPHIN/2015/66998, e-mail: vijaymat.bhopal@gmail.com। मोबाइल- +91 88899 77997